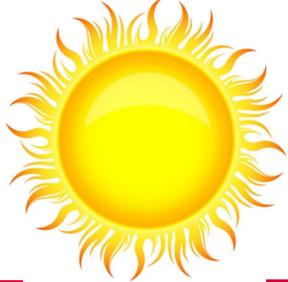


दैनिक दिव्य सांवाद

वर्ष 01 अंक: 52

उज्जैन सोमवार दिनांक 30 मार्च 2026 फालगुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत् 2083

पृष्ठ: 8 मूल्य :02 रुपये



मौसम आज

तापमान

न्यूनतम - 22 डि.से.

अधिकतम - 36 डि.से.

न्यूज गैलरी

इयूटी में लापरवाही पड़ी भारी, देहरादून में एसएसपी ने दरोगा को किया सस्पेंड



नई दिल्ली (एजेंसी)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए एक उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई इयूटी के दौरान पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करने के आरोप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 मार्च 2026 को थाना रायपुर क्षेत्र में एक पीआरडी कर्मी को आत्महत्या के मामले के बाद कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी क्रम में थाना डालनवाला से उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह को इयूटी पर नियुक्त किया गया था। इयूटी के दौरान उपनिरीक्षक द्वारा अपेक्षित आचरण और अनुशासन का पालन न करने की शिकायत सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी देहरादून ने तत्काल संज्ञान लिया और बिना देरी किए उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया।

रणजी की जीत और आकिब नबी की रफ्तार के मुरीद हुए पीएम मोदी



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत की हालिया खेल उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विशेष रूप से जम्मु-कश्मीर की सराहना की और कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश तेजी से खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनकर उभर रहा है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मु-कश्मीर की ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि टीम ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। कर्नाटक में खेले गए फाइनल मुकाबले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार सात दशकों के बाद यह पहली बार है जब जम्मु-कश्मीर ने यह खिताब अपने नाम किया।

झारखंड में आयुष्मान योजना के नाम पर अस्पतालों से ठगी, फोन कर बनाया जा रहा निशाना; स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। झारखंड में स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार के साथ साइबर ठगी का नया और संगठित रूप सामने आया है। अब ठगों ने आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

राज्य के कई पैन्ल अस्पतालों को फर्जी काल कर खुद को स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का करीबी बताने वाले लोग संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठगी बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही है। फोन करने वाला व्यक्ति पहले अस्पताल प्रबंधन का विश्वास जीतता है और फिर यह दावा



करता है कि अस्पताल के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज हुई है या केंद्र से जांच टीम आने वाली है।

कई बार यह भी कहता है कि अस्पताल के आयुष्मान क्लेम में गड़बड़ी

पाई गई है और मामला गंभीर है। इसके बाद वह मामले को सुलझाने के नाम पर पैसे या सिस्टम से जुड़ी गोपनीय जानकारी मांगता है।

आयुष्मान का झारखंड में व्यापक विस्तार- राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का व्यापक विस्तार हुआ है, वहां इस तरह की ठगी की आशंका अधिक हो जाती है। राज्य में बड़ी संख्या में निजी और सरकारी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं और क्लेम व भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। यही

कारण है कि साइबर अपराधी इस सिस्टम की कमजोर कड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने की चेतावनी- स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अस्पतालों और संबंधित संस्थानों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी फोन पर इस तरह की जानकारी या पैसे की मांग नहीं करता। आयुष्मान योजना पूरी तरह कैशलेस है और सभी आधिकारिक संवाद केवल सत्यापित माध्यमों से ही किए जाते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध फोन या मैसेज को तुरंत नजरअंदाज कर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की सलाह दी गई है।

नकली प्रोटीन सप्लीमेंट रैकेट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले हुई थी दो आरोपियों की गिरफ्तारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली प्रोटीन सप्लीमेंट रैकेट मामले में नवीन कुमार उर्फ बंजारा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिछली कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने मोहित तिवारी और मोहित दीक्षित नाम के दो आरोपित को गिरफ्तार किया था और उनसे 150 किलोग्राम नकली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तथा कई ब्रांडों के जाली स्टिकर बरामद किए गए थे। इस बार टीम ने हरियाणा के नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज



कुमार के मुताबिक पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों से पृष्ठताछ के आधार पर इस्पेक्टर रामपाल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी विश्लेषण व स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को नवीन कुमार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर रानी

खेड़ा गांव स्थित एक परिसर पर छाप मार वहां नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने और उनकी पैकेजिंग करने में लगी एक और अवैध निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। जांच से पता चला कि वह विभिन्न कच्चे पाउडर और फ्लेवोरिंग एजेंटों को मिलाकर आर्टिफिशियल और सिंथा-6 जैसे नामी ब्रांडों के नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बना रहा था, और उन्हें जाली स्टिकर, होलोग्राम और सील का उपयोग करके नकली डिब्बों में पैक कर रहा था।

भगवान महावीर के विचार आज भी हैं प्रासंगिक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दिगंबर और श्वेताम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन ने दी है समाज सेवा को नई दिशा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर संसार को सत्य, अहिंसा, अस्वंचय, अपरिग्रह, त्याग और तपस्या का शाश्वत संदेश देने वाले करुणा के महासागर थे। भगवान महावीर ऐसे तीर्थंकर हैं, जिनसे हम सबको प्रेरणा मिलती है। ऐसे भगवान की जयंती हमें वर्षभर मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज से करीब द्वाद्विंशति हजार साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा था, वह आज की वैश्विक परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है। जैन दर्शन की विशेषता है कि वह दूसरों को दबाने या डराने के बजाय, जिनेन्द्रियों पर अर्थात् स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। भगवान महावीर स्वामी ने भी स्वयं की इन्द्रियों को जीता है, इसलिये वे जिन महावीर कहलाये। आज पूरी दुनिया उनको पूजती है, उनके विचारों को मानती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान महावीर के चरणों में वंदन कर प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हर काल में राष्ट्र निर्माण में जैन समाज का अप्रतिम योगदान रहा है। आज ऐसे समाजसेवियों को सम्मानित करना हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है, जिन्होंने भगवान महावीर की शिक्षाओं को अपने आचरण और व्यक्तित्व में उतारा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इन्दौर में श्री मदन मोहन मेहता ऑडिटोरियम में महावीर जयंती व्याख्यान एवं महावीर अलंकरण/सम्मान समारोह



के संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान जिन महावीर पर दिखाए सत्यमार्ग पर चलने वाले 4 वरिष्ठ समाजसेवियों श्री चंदनमल चौरडिया, श्री हंसराज जैन, श्री हंसमुख गांधी एवं श्री संतोष कुमार जैन को %महावीर अलंकरण% प्रदान किया। साथ ही सम्मानित समाजसेवियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सबने भगवान महावीर के सिद्धांतों को सच्चे अर्थों में जीवन में आत्मसात किया है। आपका आचरण और यह उपलब्धि दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दिगंबर जैन

सोशल ग्रुप फेडरेशन और श्वेताम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन उच्च कोटि की समाज सेवा के जीवंत उदाहरण हैं। महावीर जयंती व्याख्यान एवं महावीर अलंकरण समारोह के रूप में इन दोनों फेडरेशन्स का यह संयुक्त प्रयास अद्भुत संगठन शक्ति, समर्पण और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्तमान में चल रहे वैश्विक उथल-पुथल का जिक्र करते हुए कहा कि स्वहितों के लिए पूरे विश्व को विषम और असामान्य सी परिस्थितियों में ला देने वाले लोगों को भगवान महावीर के %अहिंसा परमो धर्म% सूत्र वाक्य को याद करना चाहिए। क्योंकि हिंसा और अराजकता का जबाब प्रतिकार नहीं, बल्कि करुणा और संयम ही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि करीब 100 साल पहले विदेशियों को संबोधित करते हुए महान वैज्ञानिक डॉ. जगदीश चन्द्र बसु ने बताया था कि पेड़-पौधों में भी जीवन होता है और वे इसका अनुभव करते हैं। हमारे यहां गांव-देहात में रहने वाला सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि संस्था के समय पेड़-पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए अथवा पत्तियों और पुष्पों को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे

देश में चर-अचर जगत् में सभी को सम्मान दिया जाता है। पृथ्वी को माता मानकर उसकी पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और जैन दर्शन में पांच जिनेन्द्रियों, पांच क्रमेन्द्रियों और मनुष्य के मन-मानस को विस्तार से परिभाषित किया गया है। जैन दर्शन में एकात्मवाद सहित उपवास, आत्मा, संस्कार आदि पर भी बहुत कुछ लिखा-कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। जैसा आहार होगा, वैसा ही हमारा मन और विचार होंगे। परमात्मा ने एक चीज हम सबको दी है और वह है ऑक्सिजन, जो हम सबके जीवन के लिए जरूरी है। आज हमारी ऊर्जा का स्रोत भी सात्विक होना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाजजनों के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को शिक्षाविद् श्री स्वप्निल कोठारी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश चलावत ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विश्वधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री मनोज पटेल, श्री गोशु शुक्ला एवं श्री सावन सोनकर, श्री सुमित मिश्रा, श्री श्रवण चावड़ा, श्री हरिनारायण यादव, श्री टीनु जैन, श्री सूरज कैरो सहित जैन समाज के संतगण, दोनों ही फेडरेशन्स के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।

नोएडा एयरपोर्ट से पूर्वांचल के इस जिले को मिलेगा सीधा लाभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के विकास पथ पर शनिवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार हुआ यह अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राज्य को वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए 'नए उत्तर प्रदेश की 'उड़ान' का प्रतीक बनेगा और वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को गति देगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जनपद को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक लाभ होगा। जैसे जिले के प्रमुख उत्पाद (ओडीओपी ब्लैक पाटरी व रेशमी साड़ी) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी। स्थानीय उद्योग, कृषि व सेवा क्षेत्र को नई गति मिलेगी। निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढेंगे।



बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जनपद के उद्यमियों व व्यवसायियों ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश व जिले के लिए एक सीमांत बताया। कहा कि यह यूपी व जनपदवासियों के लिए गौरवावित होने का अवसर है। क्या कहते हैं व्यवसायी- सदगुरु एगो इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर यश जायसवाल ने कहा कि जेवर

एयरपोर्ट बन जाने से उद्यम को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे कनेक्टिविटी बढेगी और दिल्ली के बजाय पर अब जेवर एयरपोर्ट से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध होंगी। परफार्मेंस इंडिया कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव पांडेय ने बताया कि अब दिल्ली जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। जिससे समय की बचत के साथ व्यापार को भी गति मिलेगी।

जनपद के ओडीओपी ब्लैक पाटरी व रेशमी साड़ी से निर्माताओं व व्यवसायियों ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनने से व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होंगे, जिससे उद्यमियों एवं व्यापारियों को व्यापक लाभ मिलेगा। यह परियोजना प्रदेश के हर जनपद को वैश्विक मंच से जोड़ते हुए लोकल से ग्लोबल की अवधारणा को साकार करेगी। युवाओं, विद्यार्थियों, स्टार्टअप करने वाले नए उद्यमियों आदि को भी इससे लाभ होगा।

एयर इंडिया और ट्रैवल एजेंट पर हर्जाना; हवाई यात्रा रद्द होने पर रिफंड देरी पड़ी भारी



नई दिल्ली (एजेंसी)। हवाई यात्रा रद्द होने पर रिफंड देरी से देना एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट को महंगा साबित हुआ है। जिला उपभोक्ता आयोग एक शिकायत पर फैसला सुनाते हुए एयर इंडिया एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग ने सेक्टर-39 निवासी अमित अरोड़ा की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है। उन्होंने पांच साल पहले आयोग में केस

दायर किया था। अरोड़ा ने शिकायत में बताया था कि उन्होंने जून 2020 में परिवार सहित केन्या जाना था। इसके लिए उन्होंने 97748 रुपये में चार टिकट बुक करवाई थी। उन्होंने 27 जून 2020 को जाना था और आठ जुलाई 2020 को उनकी वापसी थी। कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और यात्रा रद्द कर दी गई। उन्होंने एयरलाइन से रिफंड मांगा, लेकिन उन्हें समय पर रिफंड नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता को रिफंड पाने के लिए लगातार संपर्क करना पड़ा। हालांकि एयरलाइन ने मार्च 2021 में ही पूरी राशि एजेंट को लौटा दी थी, लेकिन एजेंट ने पूरी रकम रिफंड नहीं की। ऐसे में उन्होंने उपभोक्ता आयोग में केस दायर कर दिया।

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने खड़ा किया अवैध ड्रग का कारोबार, दिल्ली पुलिस ने 4.5 करोड़ की नशीली दवा समेत 5 को दबोचा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक संगठित ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ कर चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, एक नाबालिग को भी पुलिस ने धर दबोचा है। इनमें एक पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और अन्य आरोपित दवा के अलग-अलग धंधे से जुड़े हुए थे। सभी ने जल्द अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का अवैध कारोबार शुरू कर दिया था। इस अवैध धंधे ने सभी को हवालात पहुंचा दिया। इनकी निशानदेही पर 3.5 करोड़ की 3.539 किलोग्राम अल्फ्राजोलम टैबलेट व एक करोड़ की 1.709 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट और केम्पूल बरामद की गई है। डीसीपी राहुल अलवाल के मुताबिक गिरफ्तार



किए गए आरोपितों में नितिन पाठक, उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है और बीएसपी प्रेजुएंट है। वह पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था, जहां उसे डॉक्टर की पेशी पर मिलने वाली दवाओं की भारी मांग के बारे में पता चला और उसने तेजी से रुपये कमाने के लिए अवैध रूप से दवाओं की सप्लाई का धंधा शुरू कर दिया।

प्रेम सिंह यादव, मंडोली का रहने वाला है और 12वीं पास है। वह पिछले तीन साल से भोपाल में एक मेडिकल स्टोर चला रहा था। उसी दौरान उसके अवैध सप्लायरों से तार जुड़ गए थे। इसके बाद वह बिना वैध दस्तावेज के दवाएं बेचने लगा। शालू कुमार, लक्ष्मी नगर का रहने वाला है और 10वीं पास है। उसने 2018 में एक दवा कंपनी शुरू की थी, जो कोरोना के लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई। इसके बाद, उसने जेनेरिक और जबरदस्त की पेशी पर मिलने वाली दवाओं के अवैध धंधे में कदम रख दिया। संजय सिंह, 2019 से 2021 तक भागीरथ प्लेस में मजदूर के तौर पर काम किया, जिसके बाद उसने अपना खुद का दवा सप्लाई का बिजनेस शुरू किया और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गैर-कानूनी धंधों में शामिल हो गया।

नकली प्रोटीन सप्लीमेंट रैकेट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले हुई थी दो आरोपियों की गिरफ्तारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली प्रोटीन सप्लीमेंट रैकेट मामले में नवीन कुमार उर्फ बंजारा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिछली कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने मोहित तिवारी और मोहित दीक्षित नाम के दो आरोपित को गिरफ्तार किया था और उनसे 150 किलोग्राम नकली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तथा कई ब्रांडों के जाली स्टिकर बरामद किए गए थे। इस बार टीम ने हरियाणा के नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज



कुमार के मुताबिक पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों से पृष्ठताछ के आधार पर इस्पेक्टर रामपाल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी विश्लेषण व स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को नवीन कुमार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर रानी

खेड़ा गांव स्थित एक परिसर पर छाप मार वहां नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने और उनकी पैकेजिंग करने में लगी एक और अवैध निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। जांच से पता चला कि वह विभिन्न कच्चे पाउडर और फ्लेवोरिंग एजेंटों को मिलाकर आर्टिफिशियल और सिंथा-6 जैसे नामी ब्रांडों के नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बना रहा था, और उन्हें जाली स्टिकर, होलोग्राम और सील का उपयोग करके नकली डिब्बों में पैक कर रहा था।

विकसित भारत के लिए हमें अपनी भूमिका तय करनी होगी- डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा

विकसित भारत के लिए शोध और शिक्षा महत्वपूर्ण है - प्रो. मधुकरभाई एस. पाडवी

उज्जैन। सन् 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन जिस तेजी से हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की अगर हम तुलना विकसित देशों से करें तो हमारी आय बहुत कम है, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार कृषि पर आधारित है। अगर कृषि को उद्योग का साथ मिल जाए और हम निर्यात पर जोर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

उक्त विचार मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च केंद्र के सभागार में सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेल्फेयर एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय युवा आर्थिक परिषद एवं मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में युवा आर्थिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद के सचिव डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा ने व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि 2047 में युवाओं की बड़ी आबादी होगी, युवाओं को शिक्षा और



स्कूल देने की आवश्यकता है। हमें रोजगार के नए-नए अवसर की ओर ध्यान देना होगा। आयात पर नियंत्रण कर निर्यात पर ध्यान देना होगा। चीन और रूस जैसे देशों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। विकसित भारत 2047 सरकार के साथ समाज को भी भूमिका तय करनी होगी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य

अतिथि के रूप में प्रो. मधुकरभाई एस. पाडवी-अध्यक्ष आईसीएसएसआर दिल्ली और कुलपति, बिरसा मुंडा जनजाति विश्वविद्यालय गुजरात ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवाओं को कौशल मिलेगा और देश तेजी से विकास करेगा। शोध और नवाचार से भारत वैश्विक स्तर

पर मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के लिए शोध और शिक्षा महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर प्रो. यतींद्र सिंह सि सो दि या - डायरेक्टर एम.पी.आई.एस.एस.आर. ने ग्रामीण विकास की समस्या और समाधान पर अपना विषय रखा। प्रो. बी.पी. वीरभद्रा-पूर्व कुलपति, कुवेम्पु विश्वविद्यालय कर्नाटक, प्रो. अप्पण भारद्वाज-कुलपति सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, डॉ. ब्लेस मारिकर बी. रामोस-फिलीपींस, प्रो. एस. के. मिश्रा, गौरव धाकड़ा आदि ने भी संबोधित किया।

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में डॉ. लोकेश्वर सिंह जोधाना, डॉ. विनोद सेन, प्रो. उत्सव आनंद, डॉ. आर.वी. रेड्डी, डॉ. दिलीप सिंह, डॉ. अंजली तिवारी आदि ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी में देश-विदेश के लगभग 136 से अधिक प्राध्यापक एवं शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रवीण कुमार झा ने किया।

एआई से कम समय में होगा सटीक बैंक ऑडिट, धोखाधड़ी रोकने पर मंथन



उज्जैन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड के अंतर्गत उज्जैन सीए ब्रांच द्वारा स्टैच्यूटी बैंक ऑडिट विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। ब्रांच चेयरमैन सीए आशीष तोतला ने बताया कि प्रतिवर्ष बैंकों का स्टैच्यूटी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता है। सीए सदस्यों को ऑडिट से संबंधित नवीनतम

अपडेट और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद के सीए प्रेमनाथ और लातूर के सीए राहुल उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान में वित्तीय धोखाधड़ी के नए तरीके सामने आने से बैंक ऑडिट अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने समझाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से कम समय

में अधिक सटीक ऑडिट कैसे किया जा सकता है। साथ ही बैंकिंग के उन क्षेत्रों की जानकारी दी, जहां जोखिम अधिक रहता है और जिनका सूक्ष्म परीक्षण करना आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन सीए आतुश जैन और सीए अनीश चौधरी ने किया। अतिथियों का सम्मान सीए आकृत जैन और सीए मनीष राठौं ने किया। यह सेमिनार उपस्थित सीए सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।

अघोर अखाड़ा एवं श्री सेनापति काल भैरव गौसेवा संगठन का अष्टधारा मंदिरा महायज्ञ 08 अप्रैल से 17 अप्रैल तक



उज्जैन। काल भैरव घाट स्थित श्री बम-बम भूतेश्वर महादेव मंदिर में अघोर अखाड़ा कुंजार शर्मा की सेनापति काल भैरव गौसेवा संगठन उज्जैन के तत्वावधान में 08 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक अष्टधारा मंदिरा महायज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में देश-विदेश से बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालुओं एवं साधक

साधिकाओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है, जिसके मद्देनजर मंदिर समिति द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ेधरी अघोरी बाबा योगी विष्णु नाथ महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि महायज्ञ का मुख्य स्वरूप 'मंदिरा अर्पण' है। इसका मतलब नशा या दिखावा नहीं अर्पित प्रतीकात्मक रूप से तामसिक प्रवृत्तियों-काम,

क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार-का त्याग कर भगवान काल भैरव के चरणों में समर्पित करके समाज व देश को उज्वल भविष्य की कामना करने के लिए है। इस महायज्ञ का उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण, मानसिक संतुलन एवं समाज कल्याण की भावना को बढ़ावा देना है।

साथ ही, इसके माध्यम से सेवा, त्याग, परोपकार एवं सनातन धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया जाएगा। आयोजन के दौरान प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक एवं तांत्रिक अनुष्ठान, पूजन-अर्चन एवं श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी भंडारे की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम में देशभर से कई अखाड़ों के संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजक मंडल एवं सेनापति गौ सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत निकी टांक ने सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस धार्मिक आयोजन में पुण्य लाभ अर्जित करें एवं आयोजन को सफल बनाएं।

सिंहस्थ महापर्व के अस्थायी कार्यों के लिए एक समग्र एवं प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए- संभागायुक्त श्री सिंह

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों ने पकड़ा जोर, अस्थायी कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित

उज्जैन। सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को गति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंहस्थ के दौरान किए जाने वाले विभिन्न अस्थायी कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अस्थायी कार्यों की समीक्षा करते हुए मेला क्षेत्र के समतलीकरण, जल प्रदाय व्यवस्था, घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी शौचालय एवं खानगृह निर्माण, कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन,



शहर के सौंदर्यकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों द्वारा इन कार्यों के क्रियान्वयन की रूपरेखा एवं संभावित चुनौतियों पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए।

संभागायुक्त सह मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपने-अपने प्रस्तावित अस्थायी कार्यों की सूची अंतिम रूप में शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि समयबद्ध तरीके से कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अस्थायी कार्यों के लिए एक समग्र एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में जिला कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह एवं नगर निगम आयुक्त श्री अमिताभ मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वास्तु सलाहकार पारस जैन आचार्य वराहमिहिर सम्मान से अलंकृत

विचार क्रांति साहित्य मंच ने मनाई जयंती, चार अन्य साहित्यकारों का भी हुआ सम्मान

उज्जैन। खगोलविद् आचार्य वराहमिहिर की जयंती चैत्र शुक्ल विजयादशमी के अवसर पर शहर के साहित्यकारों ने हर्षोल्लास के साथ उन्हें स्मरण किया। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के वाग्देवी भवन सभागृह में विचार क्रांति साहित्य मंच कायथा द्वारा जयंती एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

संस्था अध्यक्ष सुगनचंद जैन ने बताया कि समारोह कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता, संस्कृत विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष तुलसीदास परोहा, प्रेमचंद सुजन पीठ के निदेशक मुकेश जोशी, चित्रकार श्रीकृष्ण जोशी और प्रोफेसर जगदीश शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आचार्य वराहमिहिर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचर्चा की गई। इस दौरान कायथा निवासी वास्तु सलाहकार और ज्योतिर्विद् पारस जैन को आचार्य वराहमिहिर सम्मान 2026% से अलंकृत किया गया। इसी क्रम में



साहित्यकार दिलीप जैन को साहित्य महारथी सम्मान, सत्यनारायण नाटणी सत्येंद्र को साहित्य सारथी सम्मान, अक्षय चवरे को साहित्य भारती सम्मान और नवीदित कलमकार तरुण उपाध्याय तरुण

को साहित्य विद्यार्थी सम्मान प्रदान किया गया। ज्ञान को विज्ञान से जोड़कर विश्व को किया प्रकाशमान मुख्य अतिथि ने कहा कि वराहमिहिर

स्वयं एक सक्षम साहित्यकार थे। उनकी जयंती पर साहित्यकारों का सम्मान उन्हें सच्ची पुष्पांजलि है। अध्यक्षीय उद्घोषण में प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि नवरत्नों में श्रेष्ठ रत्नशिरोमणि वराहमिहिर सिर्फ ज्योतिष के ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि वे विज्ञान की ऐसी प्रयोगशाला थे जिन्होंने अपने ज्ञान को धर्म और विज्ञान से जोड़कर ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनकी रश्मियों से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशमान हुआ है।

कविताओं के माध्यम से दी भावांजलि कार्यक्रम में ज्योतिष विचार मंच के सचिव संजीव पांचाल भट्टनी, अजमेर के ज्योतिषाचार्य राजेंद्र गुप्ता, आगरा के ज्योतिर्विद् राजेंद्र शर्मा और इंदौर के नंदकिशोर चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों के व्याख्यान के पश्चात

साहित्यकारों ने काव्य पाठ किया। खूबसूरत बाफना ने सरस्वती वंदना और आचार्य वराहमिहिर पर कविता का वाचन किया। डॉ. रमेशचंद्र चागोंसिया, रमेश मंदीरिया मयंक, नंदकिशोर पांचाल, संगीता तल्लेरा, शारदा श्री और अनिल पांचाल ने आचार्य की जन्मभूमि को रेखांकित करते हुए कविताएं पढ़ीं। वरिष्ठ कवि अशोक भाटी ने शिखर कलशा कविता प्रस्तुत की।

बैकर्स संस्था प्राची के डायरेक्टर व व्यवहार शाशांक दुबे और जीएल निगम से सम्मानित साहित्यकारों को पुष्पमाला पहनाकर अपनी संस्था की ओर से सम्मान किया। मुकेश जोशी, सेवानिवृत्त शिक्षक मदनलाल राठौर, कृष्ण कान्त नागर, राजेश जैन और सेजमल कछवाय ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। संस्था प्रमुख सुगनचंद जैन ने काव्यमय प्रस्तुति के साथ आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विचार क्रांति साहित्य मंच के संयोजक अनिल पांचाल सेवक ने किया।

डॉ. अभिषेक दास महाराज बने हिंदुत्व रक्षा महासंघ के जिलाध्यक्ष



उज्जैन। हिंदुत्व रक्षा महासंघ द्वारा संगठन विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उज्जैन में महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रख्यात कानूनविद् एवं आध्यात्मिक विचारक डॉ. राव बहादुर सिंह ने महामंडलेश्वर आचार्य डॉ. अभिषेक दास महाराज को वर्ष 2026 के लिए उज्जैन का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष से संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा और अनुशासन के साथ कार्य करते हुए हिंदुत्व एवं गौसेवा के अभियान को गति प्रदान करने की

कार्यकारिणी का गठन करने का दायित्व भी सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जिले और राज्यभर से बधाइयों का दौर शुरू हो गया है और उनके निवास पर मिलने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

अपेक्षा की गई है। साथ ही, वे संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्हें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़कर शीर्ष नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुरूप जिला कार्यकारिणी का गठन करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार और सुविधाओं पर उदात्त सवाल-जापान में आरोप लगाया गया है कि मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ अभद्रता करते हैं, अतः उन्हें हटाना जाए। साथ ही सेना की वर्दी जैसी ड्रेस पहनने वाले गार्ड्स की ड्रेस में बदलाव की मांग की गई है। गर्मी के कारण गेट नंबर 1 और मानसरोवर गेट पर भक्तों के पैर

महाकाल मंदिर में गेट नंबर 4 से प्रवेश रोकने पर आक्रोश



उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में नित्य दर्शनार्थियों को गेट नंबर 4 से प्रवेश देने पर रोक लगाने और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर नित्य दर्शनार्थी भक्त मंडल ने मंदिर प्रशासक को ज्ञापन सौंपा है। भक्त मंडल के अध्यक्ष रवि राय के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि नित्य दर्शनार्थियों की दर्शन व्यवस्था गेट नंबर 4 से ही रखी जाए, वरना बुधवार को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रवि राय ने बताया कि 29 मार्च को नित्य दर्शनार्थियों को गेट नंबर 4 से प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें गेट नंबर 1 से जाने के लिए कहा गया। इस नई व्यवस्था से भक्तों को काफी परेशानी हुई और वे मंदिर परिसर स्थित कोटेश्वर महादेव के दर्शन से भी वंचित रह गए।

जलने की समस्या का उल्लेख करते हुए वहां पेयजल, छाया और स्थायी जूते-चपल स्टैंड की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा गेट नंबर 4 के सामने कई दिनों से बंद पड़े दीवार के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की बात कही गई है। निशुल्क लड्डू प्रसादी और विष्णु प्रतिमा की स्थापना की मांग भक्त मंडल ने प्रमुख मांग रखते हुए कहा है कि संध्या आरती और शयन आरती में जो 250 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है, उसके बदले भक्तों को लड्डू का प्रसाद निशुल्क दिया जाना चाहिए। शंख धरिता के साथ आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विचार क्रांति साहित्य मंच के संयोजक अनिल पांचाल सेवक ने किया।

नवीन आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। वकीलों, महिलाओं और भक्तों ने दर्ज कराया विरोध-इस ज्ञापन में बड़ी संख्या में वकीलों, महिलाओं और भक्तों ने अपने हस्ताक्षर कर समर्थन जताया है। इनमें रवि राय, महेंद्र कटियार, अधिवक्ता मनीष मनाता और अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह परिहार सहित कई वकील मौजूद रहे। महिलाओं में पिकी यादव, मंजू शर्मा, अल्का मिश्रा, साधना चौहान, रेखा मिश्रा, ज्योति चौहान, रूपाली अग्रवाल, गायत्री कुशवाहा, चंद्रकांता मीणा, निशा राठौर और आशा सूर्यवंशी शामिल थीं। इसके साथ ही अनिंदु पुरा गंगवार, जितेंद्र सिंह गंगवार, प्रीतम सिंह चंदेल, अंकित भावसार, दीपक जोशी, रवि मेवाड़ा, ब्रजमोहन मिश्रा, गोपाल शर्मा और नीलेश शर्मा आदि ने भी अव्यवस्थाओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

संपादकीय

प्रतिस्पर्धा से परे शिक्षा

आज की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा अक्सर शैक्षिक प्रणालियों पर हावी हो जाती है, जिससे यह तय होता है कि छात्र कैसे सीखते हैं और उनकी सफलता कैसे मापी जाती है। जबकि प्रतिस्पर्धा प्रेरणा और नवीनता को बढ़ावा दे सकती है, यह अनुचित तनाव भी पैदा कर सकती है, रचनात्मकता को दबा सकती है और सहयोग में बाधा डाल सकती है। शिक्षा को प्रतिस्पर्धा से परे स्थानांतरित करने में अधिक समावेशी, छात्र-केंद्रित और विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।

1. व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें- वैयक्तिक शिक्षण व्यक्तिगत रुचियों, शक्तियों और सीखने की शैलियों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना, जिससे छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति मिलती है।

आंतरिक प्रेरणा- छात्रों को बाहरी पुरस्कार या रैंकिंग के बजाय जिज्ञासा और आत्म-सुधार के लिए सीखने के लिए प्रोत्साहित करें।

2. तुलना की अपेक्षा सहयोग- टीमवर्क-उन्मुख परियोजनाएँ- डिजाइन गतिविधियाँ जो व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय सहयोग और सामूहिक समस्या-समाधान पर जोर देती हैं।

सहकर्मी शिक्षण- आपसी समझ और साझा विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकर्मी से सहकर्मी शिक्षण की सुविधा प्रदान करें।

3. समय मूल्यांकन- पोर्टफोलियो-आधारित मूल्यांकन-मानकीकृत परीक्षाओं को उन तरीकों से बदलें जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहित छात्र के समग्र विकास को प्रदर्शित करते हैं।

ग्रेड पर फीडबैक- रचनात्मक फीडबैक प्रदान करें जो संख्यात्मक या अक्षर ग्रेड के बजाय सुधार के क्षेत्रों पर केंद्रित हो।

4. भावनात्मक और सामाजिक विकास- माइंडफुलनेस प्रैक्टिस-माइंडफुलनेस, ध्यान और भावनात्मक जागरूकता कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करें।

संघर्ष समाधान कौशल- छात्रों को सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देने हुए विवादों और मतभेदों को रचनात्मक ढंग से हल करना सिखाएं।

5. अंत:विषय और अनुभावत्मक शिक्षा- वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग- छात्रों को सामुदायिक परियोजनाओं, इंटरनैशियल और व्यावहारिक अनुभवों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें।

अंतर-अनुशासनात्मक संबंध-ज्ञान की अधिक एकीकृत समझ को बढ़ावा देने के लिए विषयों के बीच की सीमाओं को धुंधला करें।

6. समावेशिता और पहुंच- सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन (यूडीएल)- विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने वाली शिक्षण विधियों और सामग्रियों का विकास करें।

अक्सर में समानता-सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों को, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण संसाधनों और समर्थन तक पहुंच हो। प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने के लाभ- तनाव में कमी- छात्र साथियों से बेहतर प्रदर्शन करने के लगातार दबाव के बिना अपनी सीखने की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

बढ़ी हुई रचनात्मकता- एक सहायक वातावरण जोखिम लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। मजबूत समुदाय-सहयोग अपनेपन और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। आजीवन सीखना- छात्र ऐसे कौशल और दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रेरित करते हैं। प्रतिस्पर्धा से परे शिक्षा की पुनर्कल्पना केवल स्कूलों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि सहयोग, समानता और प्रत्येक व्यक्ति की विविध क्षमता को महत्व देने के लिए समाज को नया आकार देने के बारे में है।

अर्थव्यवस्था में तेजी के मुश्किल है विकल्प

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकार की आय और व्यय के रद्धानों की अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो इस दस्तावेज के पाठ में कुछ खास नहीं नजर आता है। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि चालू वर्ष की पहली छमाही में हुई राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान की करीब 52 फीसदी रही। यह पांच वर्ष के औसत से बेहतर प्रदर्शन है। इस दौरान राजकोषीय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में साल की पहली छमाही के लिए तय मानक से कम रहा। इससे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अब जबकि केंद्रीय बजट जल्दी ही पेश किया जाना है, तो उसकी तैयारी के दौरान देश की वृहद आर्थिक स्थिति खासी सहज है। यकीनन दस्तावेज तो यही बताता है कि सरकार राजकोषीय मजबूती की राह पर बढ़ रही है। इसमें कोई खास चिंता नहीं दर्शाई गई है। बहरहाल, अर्धवार्षिक समीक्षा से राहत की बात शायद पूरी तरह सच नहीं हो।

यदि इस दस्तावेज को अलग ढंग से देखा जाए तो यह ऐसी उल्लेखनीय कमियां भी सामने लाता है जो वित्त मंत्रालय को चिंतित कर सकती हैं। ऐसी कमियों वाले अधिकांश क्षेत्र वृद्धि के क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था में यह कमजोरी पिछली तिमाही में नजर आई। चुनावों के चलते कम व्यय के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक वृद्धि केवल छह फीसदी रही। चूंकि नॉमिनल वृद्धि, जैसा कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया, 10.5 फीसदी होनी थी लेकिन यह एक फीसदी से अधिक कम हो गई। ऐसे में बजट का गणित जटिल हो गया है। ये बातें अर्धवार्षिक रिपोर्ट के डेटा में सामने आई हैं।

राजस्व प्राप्तियां पांच साल के औसत से अधिक होने के बावजूद कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आता है। ऐसा इसलिए कि बीते पांच साल की इस गणना में वे असाधारण वर्ष भी शामिल हैं जब देश और दुनिया महामारी की चपेट में थी। पूंजीगत व्यय की बात करें तो वृद्धि में मदद करने वाला यह व्यय भी पहली छमाही में तुलनात्मक वर्षों की अपेक्षा कम रहा है। यह भी सरकार की दुविधा को उजागर करता है। अगर उसे वृद्धि को गति देनी है तो वह व्यय बढ़ाने का जोखिम ले सकती है।

परंतु मौजूदा वर्ष के बजट अनुमानों के आधार पर पहली छमाही में राजकोषीय घाटे के कमजोर आंकड़े, वास्तविक नॉमिनल जीडीपी को सही ढंग से परिलक्षित नहीं करते। वर्ष के अंतिम राजकोषीय घाटे की गणना इसी आधार पर की जाती है। एक वास्तविक जोखिम यह है कि व्यय के लिए पहले अनुमानित मार्ग पर वापसी भी सरकार को घाटे के लक्ष्य से गुजरने पर विवश करेगी।

जाहिर है सरकार के सामने आसान विकल्प नहीं हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि को लेकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का लालच रहेगा ताकि बजट के गणित को आसान बनाया जा सके। परंतु ऐसा करना गलत होगा। मौजूदा प्रशासन ने वृद्धि और राजस्व को लेकर तार्किक और बचाव योग्य बाह्य निष्कर्षों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। बाजारों ने इस संयम के लिए पुरस्कृत भी किया है। कड़े परिश्रम से हासिल इस प्रतिष्ठा से मिली वृहद आर्थिक स्थिरता को अत्यधिक आशावादी अनुमानों के कारण जोखिम में नहीं डालना चाहिए। आखिर में सरकार को अपेक्षाकृत कम वृद्धि (तथा राजस्व एवं व्यय) अथवा राजकोषीय लक्ष्यों को टालने के बीच चयन करना होगा। आखिर में अगर यह वर्ष वृद्धि के क्षेत्र में सकारात्मक ढंग से चौंकाते वाला साबित होता है तो अच्छा ही होगा। परंतु अब तक के आंकड़ों के आधार पर सरकार को बजट में कुछ मुश्किल चयन करने होंगे।

आत्मनिर्भर बनें शहरी स्थानीय

नगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50 फीसदी से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं और 2022-23 में सरकार से उन्हें मिलने वाली रकम 20 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई।

नगर निकायों को अधिक प्रशासनिक स्वायत्ता तथा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। नगर निकायों का राजस्व बढ़ाना वित्तीय जरूरत नहीं है बल्कि यह प्रभावी शहरी प्रशासन के लिए बुनियादी जरूरत है। नगर पालिकाएं अपने आय के स्रोतों में विविधता लाकर तथा राजकोषीय क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक सक्रिय तथा टिकाऊ शहरी प्रबंधन नीतियां तैयार कर सकती हैं।

नगरीय निकायों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन में दोहरा दृष्टिकोण शामिल होता है, जिसके तहत सरकार के उच्चतर स्तरों से वित्तीय अंतरण और स्थानीय राजस्व, अच्छे ढंग से सृजन, उपयोग तथा आवंटन जरूरी होता है। भारत में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में अधिकार और संसाधन मिले हैं।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.45 फीसदी हिस्सा वित्तीय अंतरण के तौर पर नगर निकायों को दिया जाता है। इसके उलट ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलिपींस और मेक्सिको जैसे देशों में जीडीपी का 1.6 फीसदी से 5.4 फीसदी तक नगर निकायों को मिल जाता है। यूरोपीय देशों में उन्हें जीडीपी का 6 से 10 फीसदी तक आवंटित किया जाता है। इससे पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन को सहा

देने के लिए मजबूत अंतरसरकारी राजकोषीय व्यवस्थाएं कितनी जरूरी हैं। इन अंतरराष्ट्रीय मानकों से यह भी पता चलता है कि भारत में नगर निकायों को मिलने वाला धन या वित्तीय अंतरण बढ़ाए जाने की कितनी अधिक जरूरत है। साथ ही यह भी जरूरी है कि नगर निकाय स्वयं राजस्व तैयार करें, जिसमें अभी तक वे बुरी तरह पिछड़ रहे हैं।

इस दूसरे पहलू की बात करें तो देश में नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कई चुनौतियों से जूझती है। इसमें राजस्व संग्रह कम रहना, राज्यों और केंद्र से वित्तीय अंतरण पर बहुत अधिक निर्भर होना और म्युनिसिपल उधारी में इजाफा क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक सक्रिय तथा टिकाऊ शहरी प्रबंधन नीतियां तैयार कर सकती हैं।

नगर निकायों ने जीडीपी के 0.6 फीसदी के बराबर ही राजस्व तैयार किया, जबकि राज्य सरकारों ने 14.6 फीसदी जरूरी होता है। भारत में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है 2022-23 में केंद्र से 24.9 फीसदी और राज्य सरकारों से अंतरण 20.4 फीसदी बढ़ गया। नगर निकायों की उधारी भी सबको चौंकाते हुए 363.06 फीसदी बढ़ गई है। 2019-20 में यह केवल 2,886 करोड़ रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 13,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

शहरी इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली जन सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए रिपोर्ट में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से मैपिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संपत्ति के बढ़ते मूल्य



को सही तरीके से दिखाने वाली बेहतर संपत्ति कर प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई। ध्यान रहे कि कर राजस्व का सबसे अहम स्रोत संपत्ति कर ही होता है।

स्थानीय निकाय कर से राजस्व नहीं कमा सकते, इसलिए कर के अलावा अन्य स्रोतों से राजस्व बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसके लिए रिपोर्ट महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा का उदाहरण देकर 'उपयोगकर्ता शुल्क' शुरू करने का सुझाव देती है। यह शुल्क जलापूर्ति, सफाई और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरी सेवाओं पर लगाया जा सकता है। हालिया रिपोर्ट 'म्युनिसिपल परफॉर्मंस ऑफ इंडियन सिटीज- एन इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन यूओएफ डेटा' में भारत के शहरी निकायों की चुनौतियां दी गई हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस अध्ययन में 134 नगर पालिकाओं के प्रदर्शन को कसौटी पर कसा गया है। इसमें पांच अहम अंगों जू प्रशासन, सेवा, प्रौद्योगिकी, नियोजन तथा वित्त को 20 क्षेत्रों और 100 संकेतकों पर परखा गया

है।

इस आकलन में वित्तीय स्थिति का अध्ययन अहम जानकारी देता है। इसमें नगर पालिकाओं को चार अहम पैमानों जू राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर जांचा गया है। राजस्व प्रबंधन की बात करें तो लगभग 50 फीसदी नगर पालिकाएं अपने कुल राजस्व का केवल 23 प्रतिशत स्वयं सृजित करती हैं और 'उपयोगकर्ता शुल्क' शुरू करने का सुझाव देती है। यह शुल्क जलापूर्ति, सफाई और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरी सेवाओं पर लगाया जा सकता है। हालिया रिपोर्ट 'म्युनिसिपल परफॉर्मंस ऑफ इंडियन सिटीज- एन इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन यूओएफ डेटा' में भारत के शहरी निकायों की चुनौतियां दी गई हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस अध्ययन में 134 नगर पालिकाओं के प्रदर्शन को कसौटी पर कसा गया है। इसमें पांच अहम अंगों जू प्रशासन, सेवा, प्रौद्योगिकी, नियोजन तथा वित्त को 20 क्षेत्रों और 100 संकेतकों पर परखा गया

व्यय प्रबंधन की पड़ताल करने पर नगरपालिकाओं की वित्तीय कुशलता पर और भी बारीक जानकारी मिलती है। केंद्र से मिले अनुदान का इस्तेमाल करने में नगर पालिकाओं की औसत दक्षता दर 59 फीसदी है और राज्य अनुदान के मामले में औसत दर 67 फीसदी है। अधिकतर नगर पालिकाएं कर राजस्व को सबसे पहले

वेतन पर खर्च करती हैं, जिससे उनका प्रति व्यक्ति पूर्वी व्यय कम रह जाता है।

राजकोषीय जवाबदेही में नगर पालिकाओं के अनुभव उम्मीद जगाते हैं। पिछले तीन साल से नगर पालिकाओं ने 10 फीसदी से अधिक बजट अधिशेष रखा है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने काफी वित्तीय समझदारी और स्थिरता दर्शाई है। मगर राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर मिले निष्कर्ष बड़ी व्यवस्थागत चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। 109 नगर पालिकाओं यानी करीब 81 फीसदी नगर पालिकाओं के पास स्वयं उधारी लेने या निवेश करने के अधिकार नहीं हैं। वित्तीय निर्णयों के लिए उन्हें राज्यों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसने स्थानीय शासन की स्वायत्तता बहुत घट जाती है। ये आकलन नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। इन रिपोर्ट में दी गई जानकारी नए संस्थागत ढांचे की जरूरत बताती है, जहां नगर पालिकाएं विकास की रणनीतियों के केंद्र में होनी चाहिए और उनके पास अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता भी होनी चाहिए।

नए साल में एआई से कितना बदलेगा हमारा जीवन

पिछले दिनों ओपनएआई और गुगल के बीच एक मुकाबला हुआ, जिसमें गुगल ने 12 दिनों की नवाचार चुनौती रखी और फिर अपने जेमिनी 2 एआई मॉडल के साथ मैदान में डट गई। मैं इन प्रतिस्पर्धाओं से आगे 2025 और उसके बाद के चार एआई रद्धानों की चर्चा करना चाहूंगा, जो बताते हैं कि कैसे मनुष्य और एआई जीवन, काम व रिश्तों के संदर्भ में एक-दूसरे के करीब आएं? पहला रद्धान, अब कोडिंग नई अंग्रेजी है जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी, तब हमें बताया गया कि अंग्रेजी सीखना सफलता का पासपोर्ट है। हमने ऐसा ही किया और अपने करियर व व्यवसाय में सफल रहे। बदले में हमने अपने बच्चों को यही बताया कि कोडिंग सीखना सफलता का पासपोर्ट है। इस प्रकार कोडिंग नई अंग्रेजी बन गई। इसी कारण 10 साल के बच्चे को भी पाइथन और जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए कोड कैम्प में घसीटा जाने लगा। जेनरेटिव एआई के आगमन के साथ तस्वीर बदल गई। अब हर बार जब हम चैटजीपीटी या हम जैसी किसी भी चीज से कोई संवाद करते हैं, तो वास्तव में इस कोडिंग कर रहे होते हैं, यानी अपने कुछ काम के लिए उसे निर्देश दे रहे होते हैं, चाहे वह वीडियो बनाना या लेखन ही क्यों न हो। हम इससे मशीनी भाषा के बजाय अपनी कुदरती मानवीय भाषा में बात करने लगे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसमें कोडिंग को लोकोतांत्रिक बनाने व आठ अरब लोगों को कोड करने की क्षमता है। शायद इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला कहते हैं कि मशीन की भाषा सीखने के बजाय, अब मशीनों को हमारी भाषा सीखनी होगी। एनवीडिया के जेसन हुआंग भी इससे सहमत हैं और कहते हैं कि एआई की असली क्षमता यह है कि हममें से किसी को भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार, अब अंग्रेजी या कोई भी अन्य प्राकृतिक भाषा नई कोडिंग भाषा बन जाती है।

दूसरा रद्धान, एआई नई यूआई है, यानी एआई नई यूजर इंटरफेस बन जाएगा। बिल गेट्स ने नवंबर 2023 में भविष्यवाणी की थी आपको अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग एप इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। आप अपनी डिवाइस को रोजमर्रा की भाषा में बता देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।

दरअसल, यूआई वह माध्यम है, जिससे इंसान और मशीनें एक-दूसरे से संवाद करते हैं। सरल यूआई की वजह से मशीनें के साथ ज्यादा तेज, सहज और उत्पादक रिश्ता बनाना संभव हुआ है। एआई के आने से यूआई हमारी आवाज से संचालित होगी, ठीक वैसे ही, जैसे हम किसी दूसरे इंसान से संवाद करते हैं। हम अपने रोजाना के कामों के लिए चैटजीपीटी या जेमिनी से बात करेंगे। हमारे उपकरण बदल जाएंगे, जिसमें बड़ी स्क्रीन की जगह अज्ञान प्रमुख हो जाएगा।

तीसरा रद्धान, एआई एईएन नए निर्माता हैं। जेनरेटिव एआई ऐसी तकनीक है, जो कला, कविता, लेखन जैसे रचनात्मक काम कर सकती है। इससे इंसानों की नौकरी पर संकट बढ़ गया, क्योंकि रचनात्मकता को एक विशिष्ट मानवीय कौशल माना जाता था। हालांकि, मेरा मानना है, कि जेनरेटिव एआई इंसानों में साइकिल रेस की कल्पना की, जिसमें साइकिल चलाते हुए अलग-अलग जानवर दिखाई देने की संकल्पना थी। सोरा ने उसका शानदार वीडियो बनाया। जाहिर है, यह सोरा नहीं, बल्कि कुगुल की रचनात्मकता थी। साफ है, मनुष्य व एआई मिलकर रचनात्मकता के नए युग का सृजन न करेंगे। चौथा रद्धान, एआई नया ग्राहक बनाती है। औद्योगिक क्रांति अपने साथ लेन-देन करने वाले औद्योगिक ग्राहक लेकर आई, जो शायद ही कभी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जबकि इंटरनेट ने डिजिटल संचालित ग्राहक तैयार किए। एआई के इस युग में एक नए तरह का ग्राहक उभरेगा, जो नितांत निजता के युग में जिएगा और एआई उसकी जरूरतों व ब्रांड संबंध का अनुमान एक सहयोगी के तौर पर बिना किसी भावना में बंधे हुए लगाएगा। इसका मतलब यह है कि कारोबार और मार्केटिंग में बड़ा बदलाव आएगा। जाहिर है, यह सब हमारी जीवनशैली पर काफी असरदाइ होने वाला है।

मिट्टी को हरा-भरा बनाएं



मैलाथियान जैसे प्रासंगिक कीटनाशकों की तत्काल आवश्यकता है, जिनकी आपूर्ति प्रतिबंध से प्रभावित हो सकती है।

उद्योग द्वारा दिए गए तर्क अस्वीकार्य हैं। सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ है। सरकार ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी सुरक्षा को गहन जांच और मूल्यांकन के बाद ही यह निर्णय लिया है - यह प्रक्रिया सात वर्षों तक जारी रही।

इस प्रक्रिया में कीटनाशकों के निर्माताओं से परामर्श भी शामिल था। उन्हें विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिला, जिसमें कीटनाशकों की निरंतर सुरक्षा और प्रभावकारिता को प्रदर्शित करने के लिए अध्ययन प्रस्तुत करना भी शामिल था। यदि उन्हें लगता है कि इन कीटनाशकों ने मनुष्यों, जानवरों या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वे अपने दावे को पुष्ट करने के लिए आवश्यक डेटा प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया।

एब, जिन 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, उनमें से 15 को कई वर्षों से डेटा की कमी के कारण देश में पंजीकृत कीटनाशक माना जाता है। यह दर्शाता है कि पहले दिन से ही, जिन फर्मों ने आवेदन किया और पंजीकरण प्राप्त किया, वे विनियामक को अपनी सुरक्षा और प्रभावकारिता को पुष्टा तौर पर प्रदर्शित नहीं कर सके (सौजन्य, डेटा में शून्यत्व)। ऐसा आज तक नहीं किया गया है, जिसके कारण अंततः केंद्र को उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा।

दूसरा, विभिन्न राज्यों में विकास (उन्से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राउंड जीरो पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें) ने संकेत दिया कि प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही थी। 2011 में, केरल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के आधार पर मोनोक्रोटोफॉस, कार्बोप्पूरान और एटजिन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में, महाराष्ट्र ने कपास किसानों के बीच कीटनाशक विषाक्तता की उच्च घटनाओं के कारण मोनोक्रोटोहोस और एसीफेट पर प्रतिबंध लगा दिया। 2018 में, पंजाब ने मनुष्यों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का हवाला देते हुए 2,4-डी, बेनफ्युराकार्ब, डाइकोफोल, मेथिमाइल और मोनोक्रोटोफॉस के लिए नए लाइसेंस को नहीं कहा। तीसरा, जब कीटनाशकों के बारे में निर्णय लेने की बात आती है तो खतरनाक है, तो नियामक केवल सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानदंडों पर निर्भर करता है। यह यह भी देखता है कि क्या नए और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। निर्णय लागत जैसे किसी अन्य विचार से निर्देशित नहीं हो सकता। केवल इसलिए कि किसी मौजूदा उत्पाद की कीमत कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके निरंतर उपयोग को उचित ठहराया जा सकता है, भले ही वह असुरक्षित पाया जाए। उसी तर्क से, किसी नए और सुरक्षित उत्पाद को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है - क्योंकि उसकी कीमत अधिक है। सुरक्षा से समझौता किए बिना, भले ही उपयोग के अधिशास्र पर विचार किया जाए, हमें समान आधार पर तुलना करने की आवश्यकता है। यहाँ, केवल कीमत पर ही नहीं बल्कि खुराक पर भी ध्यान देना चाहिए; इसके अलावा, फसल की उपज और फसल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव भी विचार करना चाहिए।

विजय गर्ग - केंद्र सरकार द्वारा सभी तीन मुख्य श्रेणियों, अर्थात् कीटनाशक, कवकनाशक और खरपतवारनाशक, में 27 सामान्य रूप से प्रयुक्त कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सही दिशा में उज्या गया कदम है।

भारत में कीटनाशकों, कवकनाशकों और खरपतवारनाशकों की तीनों मुख्य श्रेणियों में 27 आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले से विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से उद्योग के एक खास वर्ग में चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। इस मुद्दे और इसके प्रभावों को समझने के लिए आइए कुछ तथ्यों को क्रम से रखते हैं। कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण और उपयोग को मनुष्यों या जानवरों के लिए जोखिम को रोकने और उससे जुड़े मामलों पर प्रतिबंध लगाने के अर्थनियम (1968) के तहत विनियमित किया जाता है। पंजीकरण समिति (आरसी) - अधिनियम के तहत स्थापित - फार्मूले की जांच करने, मनुष्यों और जानवरों के लिए प्रभावकारिता और सुरक्षा के दावों को सत्यापित करने और विषाक्तता और किसी भी अन्य कार्यों के खिलाफ सावधानियों को निर्दिष्ट करने के बाद प्रत्येक कीटनाशक को पंजीकृत करती है।

समय-समय पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय - कीटनाशकों के विनियमन के लिए नोडल मंत्रालय - पंजीकृत कीटनाशकों की समीक्षा का आदेश देता है, खास तौर पर मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए इनसे होने वाले जोखिम के संदर्भ में। विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच के आधार पर, यह उचित निर्णय पर पहुंचता है कि क्या उनके निरंतर उपयोग की अनुमति दी जाए (यदि कोई अतिरिक्त सावधानी बरती जाए तो) या उनके उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए।

वर्ष 2013 में, कुल 66 कीटनाशकों के निरंतर उपयोग या अन्यथा अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जो दो या अधिक देशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में उपयोग के लिए पंजीकृत हैं। इसकी सिफारिशों के आधार पर (समिति ने 9 दिसंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की), सरकार ने वर्ष 2018 में 18 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, इसने 27 कीटनाशकों के निरंतर उपयोग की अनुमति दी, जिनकी अनुमति अद्ययनों के पूरा होने के बाद समीक्षा की जाएगी।

14 मई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में, स्त्र्भ्र-खड्डू ने इन 27 कीटनाशकों के निर्माण, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक मसौदा आदेश जारी किया और 45 दिनों में हितधारकों से

टिप्पणियाँ या सुझाव मांगे।

अधिसूचना में कहा गया है- 66 कीटनाशक, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित या प्रतिबंधित या वापस लिए गए हैं, लेकिन भारत में घरेलू उपयोग के लिए पंजीकृत हैं, की समीक्षा स्त्र्भ्र-खड्डू द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। मंत्रालय ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया और माना कि 27 कीटनाशकों के उपयोग से मनुष्यों और जानवरों को खतरा होने की संभावना है, जिससे तत्काल कार्रवाई करना समीचीन या आवश्यक हो जाता है। प्रतिबंधित किए जाने वाले कीटनाशकों में 2,4-डी, एसीफेट, एटजिन, बेनफ्युराकार्ब, ब्यूटाक्लो, कैप्टान, कार्बेन्डाजिन, कार्बोप्पूरान, क्लोरोपायरीफोस, डाइकोफोल, डाइमैथोएट, डैन्डोनेकैप, डाययूरोन, मैलाथियान, मैन्कोजेब, मेथिमाइल, मोनोक्रोटोफोस, ऑक्सिफ्लोरोफेन, पेंडिमैथालिन, क्यूनिप्रलफोस, सल्फोसल्ट्पयूरान, थायोडिक्बा, थायोफैट मिथाइल, थाइरम, जिबेथिआल और जिरिम शामिल हैं।

समिति ने उपरोक्त कुछ कीटनाशकों को अस्थायिक खतरनाक पाया है, जिनसे गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव होने की संभावना है। जैसे हार्मोनल परिवर्तन, तंत्रिका-विषाक्त प्रभाव, प्रजनन और विकासवात्मक स्वास्थ्य प्रभाव, कार्सिनोजेनिक प्रभाव और साथ ही मधुमेहसिखियों के लिए विषाक्तता जैसे पर्यावरणीय प्रभाव। अन्य के लिए, नियामक तथ्य से भी निर्देशित हुई है कि जिन सभी कीटनाशकों पर वह प्रतिबंध लगाना चाहती है, उनके लिए नए और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। जेनेरैक उद्योग (नवाचार करने वाली फर्मों के अलावा अन्य निर्माताओं का वर्णन नहीं के लिए एक व्यंजना) ने प्रतिबंध पर नाराजगी जताई है, जिसका कहना है कि इससे घरेलू बिक्री डूब वरतमान में लगभग 20,000 करोड़ रुपये में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आएगी। कीटनाशकों के निर्यात को भी मौजूदा 20,000 करोड़ रुपये पर लगभग 10 प्रतिशत का झटका लगेगा।

निर्माताओं का तर्क है कि किसान लंबे समय से इन रसायनों का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें ये किरफायती लगे हैं, जबकि विकल्प महंगे हैं और इससे खेती की लागत बढ़ेगी। उन्होंने निर्णय के समय पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि किसानों को लागूतार टिड्डियों के हमलों का सामना करना पड़ता है, खासकर हाल ही में, जिसने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में खेती को जकड़ लिया है। किसानों को

23 मीटर की ऊंचाई पर लटका 400 टन का लोहा, इंदौर के चौराहे पर दिखा इंजीनियरिंग का अजूबा



इंदौर। इंदौर के लवकुश चौराहे पर बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण में एक अहम उपलब्धि हासिल की गई है। यहां शहर की सबसे लंबी 65 मीटर की स्टील गर्ड को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। करीब 400 टन वजनी इस विशाल गर्ड को जमीन से 23 मीटर ऊंचाई पर

लगाने की जटिल प्रक्रिया करीब 12 घंटे तक चली। इस गर्ड के जुड़ने से शहर में यातायात को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लवकुश चौराहे पर बो स्ट्रिंग स्मान के निर्माण के दौरान इस भारी गर्ड को हवा में ही जोड़ा गया। इसे सही जगह तक लाने के लिए तीन विच

मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इनमें से दो मशीनों से गर्ड को आगे की ओर खींचा गया, जबकि एक मशीन को पीछे से संतुलन बनाए रखने और रोकने के लिए लगाया गया था। अब जैक पुश तकनीक के जरिए इसे दूसरी तरफ के बो स्ट्रिंग स्मान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। पहली गर्ड का काम पूरा होने के बाद अब दूसरी स्टील गर्ड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लवकुश चौराहे पर कुल 1452 मीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस परियोजना में 19 सेगमेंटल स्मान, 4 कंपोजिट गर्ड स्मान और एक खास बांटे स्ट्रिंग स्मान शामिल हैं। जिस बो स्ट्रिंग स्मान पर यह गर्ड रखी गई है, उसकी लंबाई 65 मीटर है और यहां ऐसी दो स्टील गर्ड लगाई जानी हैं। पहली गर्ड का निर्माण कार्य पूरा कर उसे तय स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। गर्ड को स्थापित करने की प्रक्रिया गुरुवार रात 11 बजे शुरू हुई, जो शुरुवार सुबह 11 बजे पूरी हुई। गर्ड को खींचकर

सही जगह तक लाने में ही करीब 5 घंटे लगे। पुलिंग शुरू करने से पहले गर्ड को रीले पर चढ़ाया गया और उसके संतुलन की पूरी जांच की गई। सुरक्षा के लिहाज से इस दौरान नीचे से गुजरने वाले यातायात को पूरी तरह बंद कर दिया गया, ताकि कोई हादसा न हो। शहर का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर पॉइंट बना आकर्षण- यह 400 टन वजनी गर्ड जिस बो स्ट्रिंग पर रखी गई है, उसकी ऊंचाई 23 मीटर है, जो इंदौर के सभी फ्लाईओवर में सबसे ज्यादा है। इस फ्लाईओवर की खास बात यह है कि इसके नीचे से मेट्रो और एक अन्य फ्लाईओवर गुजर रहा है। इसी वजह से गर्ड को ऊंचाई पर ही जोड़ना पड़ा। इस जटिल काम के लिए 900 टन की कुल क्षमता वाली दो क्रेन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक 600 टन और दूसरी 300 टन की क्रेन शामिल थी। इन्होंने क्रेन की मदद से भारी एंगल और निर्माण सामग्री को 23 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया।

मिडिल ईस्ट युद्ध का असर विद्यार्थियों के भविष्य पर, प्लेसमेंट में नहीं आई यूई की कंपनियां



इंदौर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इरान-इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव से अब सीधेतर पर विद्यार्थियों के करियर पर असर पड़ने लगा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवी) में इस साल का प्लेसमेंट सेशन विद्यार्थियों के लिए पहले जैसा नहीं है। जहां हर साल विदेशी कंपनियों की लंबी कतारें विश्वविद्यालय के कैम्पस में देखने को मिलती थीं। वहीं, इस बार कई बड़ी कंपनियों ने प्लेसमेंट गतिविधियों से दूरियां बना ली हैं। सबसे ज्यादा असर यूनाइटेड अरब

की कंपनियों ने इस साल भर्ती में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अप्रैल में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अक्सर यह देखा जाता है कि अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में विश्वविद्यालय के प्रमुख विभागों के विद्यार्थियों को नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी विपरीत है। 2025-26 सत्र में 1300 छात्र-छात्राओं ने प्लेसमेंट को लेकर पंजीयन करवाया है। प्लेसमेंट सेल के मुताबिक

आईएमएस, आईआईटी, आईआईटी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंफोआरसी के 70-80 फीसद विद्यार्थियों को नौकरियां लग पाई हैं। युद्ध के चलते वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है। इसे प्लेसमेंट थोड़े घट गए हैं। सेल सदस्यों का कहना है कि युद्ध से तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे महंगाई बढ़ी है और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। इन सेक्टर में काम करने वाली यूई की कंपनियों ने भर्तियों पर रोक लगाई है। यहां तक कि स्टाफ कम करने में लगी है। इसका सीधा असर कैम्पस प्लेसमेंट पर पड़ रहा है। कंपनियों ने विस्तार रोका- मिडिल ईस्ट पर निर्भर मल्टीनेशनल कंपनियों भी सतर्क हो गई हैं। उन्होंने अपने विस्तार और भर्ती योजनाओं को धीमा कर दिया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृहद मेगा शिविर आयोजित, 750 से अधिक नागरिकों को किया गया शासन की योजनाओं से लाभान्वित

सोहोरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोहोरे के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में मेगा लीगल आउटरीच एवं जागरूकता शिविर -संवेदना- आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरु के. और एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सहित न्यायाधीशगण शामिल हुए। इस मेगा शिविर की मुख्य थीम मानसिक स्वास्थ्य एवं दिव्यांगजनों के अधिकार रही गई, जिसमें जिले सभी विभागों द्वारा स्टाॅल लगाए गए और 750 से अधिक नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस

अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टाॅल का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, हिरियरि एंड, टीएलएम किट, बेला किट आदि प्रदान किए। मेगा शिविर में आयोजित ब्लड डोनेशन कैम्प में 15 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अग्रवाल एवं न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू ने भी रक्तदान किया। इस दौरान टीबी स्क्रीनिंग एवं एक्स-रे के माध्यम से 51 लोगों का बी.पी. शुगर चेक किया गया और 350 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने दिव्यांगजनों के अधिकार, विधिक प्रावधान,

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में विधिक सेवा संस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह संदेश दिया कि हम सभी संवेदनशील बनें एवं दिव्यांगजनों के साथ हर जरूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोगन सभी विभागों को एक मंच पर लाकर आमजन को लाभान्वित करने का एक सशक्त माध्यम है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री वैभव मंडलौरा द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम एवं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सचिव श्रीमती स्वप्नी सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आयोजन के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये बताया गया कि इस कार्यक्रम का नाम संवेदना रखा

गया क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य आमजन के मध्य संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर एनआईएमएचआर के विद्यार्थियों द्वारा नुकड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। मेगा शिविर के शुभारंभ अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अग्रवाल, कलेक्टर श्री बालागुरु के., एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री वैभव मंडलौरा, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नी सिंह, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री अनिल पारे निदेशक श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा हस्ताक्षर पट्टिका पर हस्ताक्षर किए गए और पंच ज योजना के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया।

थाने में गिड़गिड़ाने लगा महिला इंजीनियर की जान लेने वाला युवक, सोशल मीडिया पर देता था धमकियां

इंदौर। इंदौर के निपानिया क्षेत्र स्थित शिव वाटिका में सागर समृद्धि बिल्डिंग की निवासी महिला इंजीनियर शंका पाठक पांडे की हत्या के मामले में लसुड़िया पुलिस ने आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों को अब रविवार को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा। लसुड़िया थाने की हिरासत में मौजूद आरोपी मोहनेश उर्फ मोहित अब अपने किए पर पछतावा जाहिर कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लोकअप में बंद मोहनेश बार-बार रो रहा है और पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने शुरू कर रहा है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। टीआई तारेश सोनी ने बताया कि रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करेगी और चरमदोस्तों के माध्यम से उनकी शिनाख्त भी करवाई जाएगी।



जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी मोहनेश बेहद जिद्दी और विगडैल स्वभाव का है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जाट एक्स के नाम से आईडी चलाता था। इस आईडी पर वह अक्सर तेज रफ्तार ड्राइविंग और लोगों को धमकाने वाले वीडियो (रोलस) पोस्ट किया करता था। चौकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, इसके बावजूद वह बेखौफ होकर गाड़ियां दौड़ा था। थाना प्रभारी तारेश सोनी ने बताया कि

आरोपी मोहनेश और उसके पिता कुलदीप चौधरी से अभी कई बिंदुओं पर पूछताछ होनी है। पुलिस इस मामले में पुछता साक्ष्य जुटा रही है। फिलहाल बिल्डिंग के चौकीदार की पत्नी रेणुका और कुछ अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मृतका शंका के पति सौरभ और परिवार के अन्य सदस्यों के बयान दर्ज होना अभी बाकी है। पुलिस का लक्ष्य है कि पिता-पुत्र के विरुद्ध इतना ठोस केस तैयार किया जाए कि उन्हें भविष्य में कोई कानूनी राहत न मिल सके। घटनाक्रम के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि जब आरोपी और उसके पिता का विवाद चल रहा था, तब मोहित ने अपने कई दोस्तों को फोन कर मौके पर पहुंचने के लिए कहा था। वह चाहता था कि उसके दोस्त आकर विवाद में उसका साथ दें, लेकिन गनीमत रही कि उस समय कोई भी उसकी मदद के लिए वहां नहीं पहुंचा।

आईएस वंदना वैद्य के फार्महाउस पर कार्रवाई करने वाले टीआई सस्पेंड



साथ वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिए भारी दबाव बनाया गया था, जिसे मानने से इनकार करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। गुरुवार को इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हार्दिकोर्ट में हुई, जहां शासन की ओर से जवाब पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव गृह विभाग, डीजीपी, आईजी ग्रामीण, एसपी ग्रामीण, अतिरिक्त एसपी और एसडीओपी को पक्षकार बनाया है और उनसे इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता टीआई हिहोरे ने आरोप लगाया है कि उनके विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाई पूरी तरह से वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभाव में आकर की गई है और यह प्रशासनिक शक्तियों के खुले दुरुपयोग का उदाहरण है। अब इस कानूनी लड़ाई की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

याचिका में टीआई ने विस्तार से बताया है कि उन पर लगातार यह दबाव डाला जा रहा था कि वे एफआईआर से फार्महाउस का नाम हटा दें और जुआ पकड़े जाने का स्थान बदल दें। जब उन्होंने कानून के दायरे में रहकर सही तथ्य दर्ज किए, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। टीआई ने यह भी खवाल उठायी कि जांच का जिम्मा ऐसे अधिकारी को सौंपा गया है जो सीधे उन वरिष्ठों के अधीन हैं जिन्होंने मुझ पर यह कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एसआई रेशम गिरवाल के निलंबन पर भी हेरानि जताई, जो घटना के समय बीमारी की छुट्टी पर थीं और ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थीं। टीआई अनजान थे आईएस के फार्महाउस से- लोकेंद्र सिंह हिहोरे ने अपनी याचिका में यह साफ किया है कि जब उन्होंने मानपुर स्थित फार्महाउस पर दबिश दी थी, तब उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि यह संपत्ति आईएस वंदना वैद्य की है। जैसे ही यह तथ्य उजागर हुआ, उनके पास फोन कॉल्स और संदेशों के जरिए दबाव बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। गौरतलब है कि 10 और 11 मार्च की दरमियानी रात हुई इस कार्रवाई के बाद एसपी यांगचेन डोलकर भाटिया ने टीआई सहित तीन पुलिसकर्मीयों को निलंबित कर दिया था। अब 1 अप्रैल को सुनवाई इस जुआकांड में बेहद निर्णायक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार किसी अधिकारी ने विभाग के भीतर के दबाव को सार्वजनिक किया है।

इस पूरे कानूनी घटनाक्रम पर टीआई लोकेंद्र सिंह हिहोरे की वकील मिनी रवीन्द्र ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसकी अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि मामला कोर्ट में होने के कारण सुनवाई से पहले किसी भी प्रकार की विस्तृत टिप्पणी या गोपनीय जानकारी साझा करना उचित नहीं होगा। सभी पक्ष अब कोर्ट में ही अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।

इंदौर में एक ही चेहरे पर खरीदे 84 सिमकार्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीओएस एजेंट को पकड़ा

इंदौर। फर्जी तरीके से सिमकार्ड एक्टिवेट करने का फर्जीबाड़ सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) एजेंट को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी ऑपरेशन फेस के तहत हुई। पुलिस को डिपार्टमेंट आफ टेलीकॉम्युनिकेशन (टीओटी) के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स से जानकारी मिली थी। एजेंट एक ही चेहरे पर 84 से ज्यादा सिमकार्ड इशू कर एक्टिवेट करवा चुका था। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को पटेल वार्ड बैतूल निवासी विपिन मगरदे के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। डीओटी ने एआई आधारित फेस रिकग्नाइज टूल्स (एएसटीआर) से जांच करवाई और राज्य साइबर सेल को बताया कि एक



ही चेहरे (यूनिक फेस) पर 50 से अधिक सिमकार्ड नाम-पता बदल कर एक्टिवेट करवाए गए हैं। 2018 से 2021 तक पीओएस एजेंट था- आरोपी विपिन की जांच की तो एआई ने 84 सिमकार्ड इशू करवाने की पुष्टि कर दी। इसमें वीआईडी 37, एयरटेल की 46 और बीएसएनएल का एक सिमकार्ड था। गुरुवार को विपिन को पकड़ा के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि वह साल 2018 से 2021 तक पीओएस एजेंट था।

उसने सिमकार्ड अगली कानूनी कानूनी, 31 सिमकार्ड गौरी मोबाइल, एक सिमकार्ड नेहा टेलीकॉम, राजा टेलीकॉम, दो सिमकार्ड साहू टेलीकॉम को बेची हैं। पुलिस ने कंपनी से ग्राहक की जानकारी मांगी तो बताया कि सभी सिमकार्ड विपिन द्वारा स्थापित कर जारी करवाए गए थे। पुलिस के अनुसार विपिन टारगेट पूरा करने के लिए बार-बार अपने नाम से सिमकार्ड जारी करवा लेता था। उसने बहन प्रज्ञा और दोस्त लोकेश को भी सब एजेंट बना दिया था। पुलिस उससे सिमकार्ड जब्त करने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट पेश कर तीन

मेगा आउटरीच एवं विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

जबलपुर। प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया की गरिमामय उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में नालसा के विधिक सेवा कैम्प माइयूल के अनुसार मेगा आउटरीच एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मानस भवन में आयोजित हुआ। इस दौरान माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, माननीय सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री सुमन श्रीवास्तव, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री रावचन्द्र सिंह, कमिश्नर नगर निगम श्री आर. पी. अहिरवार, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा, न्यायिक अधिकारीगण, मध्यस्थगण शासन प्रशासन के अधिकारीगण, विधि एवं शिक्षा जगत के फैकल्टी एवं छात्र तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सदस्यगण एवं लाभार्थी उपस्थित

रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं मां सरस्वती के छयाचित्र पर माल्यार्पण से हुआ। अतिथियों के स्वागत के पश्चात् अतिथियों ने उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष ने शिविर की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मीडिएशन की विधा विशेष रूप से कानूनीटी मीडिएशन द्वारा विवादों के प्राथमिक स्तर पर ही समाप्त हो जाने से स्वस्थ एवं विवाद रहित समाज के निर्माण में प्रगति हो रही है। इन्दौर में कानूनीटी मीडिएशन द्वारा विवादों के समाधान का तथा हाल ही में नगर निगम के सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारीगण के कानूनीटी मीडिएशन प्रशिक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कानूनीटी मीडिएशन के संबंध में प्रकाश डाला तथा विधिक सेवा संस्थानों के मूल उद्देश्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय प्राप्त हो तथा शासन प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर लोग जीवन में ऊर्जित

प्रगति कर सके यही इन विधिक सेवा संस्थानों का मूल कार्य है। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्णमूर्ति मिश्र ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उसके महत्व पर संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा संस्थानों का कार्य केवल विधिक सेवा एवं सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, शासन के विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना तथा तालुका स्तर से सर्वोच्च न्यायलय तक सभी की न्याय तक पहुंच सुलभ एवं सुनिश्चित करना भी विधिक संस्थानों के कार्य में सम्मिलित है। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव मैडम सुमन श्रीवास्तव ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विधिक सेवा के कार्य को बताया तथा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक जागरूकता एवं सहायता द्वारा समाज में लोगों के विशेष रूप से शोषित, वंचित एवं कानूनी ज्ञान से अर्थात् लोग कैसे सशक्त बनाया जा सकता है।

ममता की छांव और उम्मीद की नई किरण : श्रीमती अनामिका जैन के सेवा संकल्प की अनकही दास्तान

भोपाल। समाज में अक्सर जिन्हें हम विधिवत कहकर अनदेखा कर देते हैं, उनके पीछे छिपी पीड़ा और खोई हुई पहचान को वापस लौटाने का बीड़ा मंदसौर की एक बेटी ने उठाया है। संजीत (मंदसौर) की रहने वाली श्रीमती अनामिका जैन आज उन बेसहारा महिलाओं के लिए मसीहा बन चुकी हैं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं था। एक छोटे से विचार से शुरू हुआ बदलाव का सफर- अनामिका जी का सेवा का सफर 17-18 साल पहले उनके पिता के साथ शुरू हुआ था। मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर चुकी अनामिका ने जब समाज के सबसे उपेक्षित तबक-निराश्रित और विधिवत महिलाओं-की स्थिति देखी, तो उनका मन पसीज गया। शुरुआत में वे सात वर्षों तक इन महिलाओं की देखरेख कर उन्हें इंदौर या उज्जैन के अनाथालयों में भेजती थीं। लेकिन कई बार जगह की कमी के कारण जब उन्हें वहां से वापस लौटा दिया जाता,



तो वह बेबसी अनामिका जी को सोने नहीं देती थी। इसी पीड़ा ने अनामिका जी जनकल्याण सेवा समिति विश्व आश्रय गृह की नींव रखी। रेवास देवड़ा रोड पर बना अपना घर- वर्ष 2018 में प्रशासन के सहयोग से उन्होंने एक शासकीय भवन (500 क्वार्टर, रेवास देवड़ा रोड) में इस आश्रय गृह की स्थापना की। यह मध्य प्रदेश का ऐसा पहला आश्रम बना, जो न केवल महिलाओं को छत देता है, बल्कि उनके पुनर्वास पर केंद्रित है। इन महिलाओं को दवा से ज्यादा

तकनीक और ममता का मेल-गुल से मिलता है बिछड़े परिवार - अनामिका जी का कार्य केवल आश्रय देने तक सीमित नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा लाई गई महिलाओं का वे इलाज करवाती हैं और उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए खेल-खेल में गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। सफलता का आँकड़ा अब तक 54 महिलाओं को ठीक कर उनके अपनों से मिलवाया जा चुका है। डिजिटल मदद- गुगल मैप्स और ऑनलाइन माध्यमों से वे उन महिलाओं के

पते ढूँढती हैं जो वर्षों से अपने घर का रास्ता भूल चुकी थीं। चुनौतियों को बनाया ताकत-मिला रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय पुरस्कार- इस कठिन मार्ग में अनामिका जी को अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनके कार्यों की गूँज शासन तक भी पहुंची। महिला उर्पीड़न को रोकने, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने और वंचितों के पुनर्वास के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भविष्य का सपना- आत्मनिर्भरता का केंद्र- अनामिका जी ने केवल आश्रय ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सपना देखती हैं। वे कुछ बस्ती और गाउँलिया बस्ती में स्कूल चलाते, महिलाओं को शराब छुड़वाने और विधवाओं को कोशल प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रही हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा विशाल पुनर्वास केंद्र बनाना है, जहाँ हर महिला को शिक्षा और रोजगार मिल सके। महिलाओं की संवेदनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक-दूसरे का हाथ थाम लें, तो कोई भी समाज असाहय नहीं रहेगा।

रुपये में रिकॉर्ड गिरावट के बीच आरबीआई ने खींच दी लक्ष्मण रेखा, बैंकों को दिया लिमिट लागू करने का निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। रुपए में गिरावट को रोकने और स्टैबलाइजि (स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग) पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नया निर्देश दिया है। आरबीआई ने अधिकृत डॉलर के रूप में काम करने वाले बैंकों को कहा है कि वे दिन के अंत तक रुपए में अपनी ओपन पोजिशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखें।



रुपए पर दबाव बढ़ने पर RBI ने उठाया कदम- यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है और रुपए पर दबाव बढ़ गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी कर्माचारियों को इस योजना लिमिट को 10 अप्रैल तक लागू करें। साथ ही, जरूरत पड़ने पर बाजार की स्थिति के अनुसार यह लिमिट बदली भी जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रुपए में गिरावट जारी रहती है तो आरबीआई आगे और भी सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रुपए को सहार देने के लिए आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन रिजर्व) का काफी इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी हस्तक्षेप करने की क्षमता को कमजोर कर दिया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है और

बाजार का वैल्यूएशन (पीई रेशियो) कम होता है, तो भारतीय बाजार में तेजी लौट सकती है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, रुपया आने वाले समय में सुधरकर करीब 91 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी मौजूदा 6.83 प्रतिशत से घटकर करीब 6.65 प्रतिशत तक आ सकती है। यह सामान्य स्थिति आने में 2-3 महीने लग सकते हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें आगे भी देश के बाहरी संतुलन को प्रभावित करंगी।

अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इससे भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है और इसका असर आर्थिक विकास और महंगाई पर भी पड़ सकता है।

ईरान के साथ अमेरिका कब खत्म करेगा जंग? मार्को रुबियो ने तय की डेडलाइन



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान महीनों नहीं, बल्कि हफ्तों में खत्म हो जाएगा और वह जमीन पर सेना तैनात किए बिना ही अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह बात शुक्रवार को विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा। फ्रांस में जी7 देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकों के बाद बोलते हुए रुबियो ने

कहा कि वाशिंगटन उस अभियान में तय समय पर या उससे आगे चल रहा है और उम्मीद है कि इसे सही समय पर खत्म कर लिया जाएगा। यह महीनों नहीं, बल्कि हफ्तों की बात है।

सैनिक भी भेजे जा रहे- उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इस क्षेत्र में कुछ सैनिक भेजे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विकल्प और ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर कोई आपात स्थिति पैदा हो तो वे उससे निपट सकें। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पूरे मध्य-पूर्व में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है।

अमेरिका के 12 सैनिक घायल - एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और सैन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित है।

इस हफ्ते सोने के बढ़े भाव तो चांदी में आई सुस्ती; क्या है इसके पीछे वजह?

नई दिल्ली (एजेंसी)। शुक्रवार को एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स में 0.15 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि एमसीएक्स सिल्वर मई फ्यूचर्स में 0.09 प्रतिशत की हल्की गिरावट आई।



अगर मौजूदा आंकड़े ही देखें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 999 प्यूरिटी वाले सोने का भाव शुक्रवार को 1,42,942 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो सोमवार के 1,35,141 रुपए से काफी ज्यादा है।

क्यों आई सोने में तेजी- वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच इस हफ्ते सोने की कीमतों में 5.77 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को स्पॉट

कि हाल में सोने में थोड़ी गिरावट इसलिए आई क्योंकि निवेशकों ने नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचकर नकदी जुटाई, लेकिन कुल मिलाकर सोने में तेजी का रुख अभी भी मजबूत बना हुआ है।

केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और वैश्विक तनाव भी कीमतों को सहारा दे रहा है। इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी पीलड बढ़ने से सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश की आकर्षकता कुछ कम हुई, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा। वहीं, इस हफ्ते ब्रेट क्रेड की कीमत करीब 120 डॉलर से गिरकर 93 डॉलर प्रति बैरल तक आई, जिससे महंगाई को लेकर चिंता कम हुई और सोने को निचले स्तर से उबरने में मदद मिली।

वे तीन द्वीप जो बदल सकते हैं होर्मुज का सत्ता संतुलन, अमेरिकी कब्जे से कमजोर पड़ जाएगी ईरान की पकड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट संकट के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को रोककर दुनिया के लिए तेल संकट खड़ा कर दिया है। होर्मुज से कुल ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20व गुजरता है, जिसे ईरान ने अवरोध कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका होर्मुज पर ईरान की पकड़ को कमजोर करने के लिए विकल्प तलाश रहा है।



एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना उन विकल्पों पर विचार कर रही है जिनमें होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित अबू मूसा, ग्रेटर तुंब और लैस्टर तुंब, इन द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य इन संकरे जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों को रोकने या उन्हें धमकाने की

इरान की क्षमता को कम करना है। ये तीनों द्वीप होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के पास स्थित हैं। 26 मार्च को रिपोर्ट के अनुसार, पेटागाम ईरान के खिलाफ एक संभावित अंतिम प्रहार के लिए कई तरह के सैन्य विकल्पों की तैयारी कर रहा है, जिसमें अबू मूसा, ग्रेटर तुंब और लैस्टर तुंब पर कब्जा करने की योजनाएं भी शामिल हैं।

इन तीनों द्वीपों पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात इन पर अपना दावा करता है। ईरान ने 1971 में, ठीक, शक के गठन से पहले, इन द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दशकों से, यह विवाद अनसुलझा बना हुआ है, लेकिन काफी हद तक नियंत्रित रहा है। 1979 से पहले खर्ग द्वीप पर सेवा दे चुके मोहम्मद फारसी ने को बताया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे इन द्वीपों पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं।

दुश्मन हमारे एक द्वीप पर कब्जे की तैयारी में- गालिबाफ ईरान की संसद के अध्यक्ष, मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक्स पर कहा था कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान के दुश्मन जिन्हें एक क्षेत्रीय देश का समर्थन प्राप्त है, उसके किसी

एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं।

कब्जे से अमेरिका को मोलभाव में मिल सकती है मदद- वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित करने से अमेरिका को जलडमरूमध्य की निगरानी अनसुलझा बना हुआ है, लेकिन सहायता करने में मदद मिल सकती है। इससे वाशिंगटन को युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली किसी भी बातचीत में मोलभाव करने की स्थिति भी मिल सकती है।

द्वीपों पर कब्जे के बाद भी जहाजों पर बना रहेगा खतरा- हालांकि, ईरान केवल इन्हीं द्वीपों पर निर्भर नहीं है। वह अपने मुख्य भूभाग से मिसाइलों, ड्रोन और नौसैनिक इकाइयों का उपयोग करके भी जहाजों को निशाना बना सकता है। इसका मतलब है कि अगर द्वीपों पर कब्जा हो भी जाता है, तो भी जहाजों के लिए खतरा बना रह सकता है।

ईरान ने होर्मुज में लगाया 2 मिलियन डॉलर का टोल, US सीनेटर बोले- ये ट्रंप का खुद का बनाया संकट



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना हुआ है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने युद्ध की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका रोजाना 2 अरब डॉलर (लगभग

17,000 करोड़ रुपये) खर्च कर रहा है, जबकि जलडमरूमध्य युद्ध शुरू होने से पहले खुला था।

मर्फी ने कहा, समस्या यह है कि जलडमरूमध्य युद्ध शुरू होने से पहले खुला था। हम अब उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने खुद

पैदा की है। यह पागलपन है! उन्होंने आगे कहा, 2 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। युद्ध पर रोजाना खर्च होने वाली न्यूनतम राशि यही है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कुछ जहाजों से 20 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) प्रति यात्रा टोल वसूलना शुरू कर दिया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरोजेदी ने राज्य प्रसारक ट्यूबट्यूब को बताया कि यह कदम युद्ध की लागत वसूलने और जलडमरूमध्य पर नई संप्रभु व्यवस्था स्थापित करने का हिस्सा है।

बोरोजेदी ने कहा, कुछ जहाजों से 2 मिलियन डॉलर ट्रांजिट फीस वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है। युद्ध की लागत है, इसलिए हमें जहाजों से फीस लेनी होगी। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई डेडलाइन को 10 दिन और बढ़ा दिया है।

क्या है अब नई डेडलाइन - ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ईरान ने किसी भी वार्ता से इनकार किया है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपना पांच सूत्री प्रस्ताव रखा है, जिसमें युद्ध के लिए मुआवजा और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता की मान्यता शामिल है। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान पर नए हमले किए और चेतावनी दी कि हमले बढ़ेंगे और विस्तारित होंगे।

वैश्विक प्रभाव- होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग एक पांचवां तेल और गैस गुजरता है। इसके बंद रहने से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर बाजार प्रभावित हुए हैं और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका-इजरायल युद्ध के चलते क्षेत्र में तनाव चरम पर है।

सीनेटर क्रिस मर्फी ने चेतावनी दी कि यह स्वयं पैदा किया संकट अमेरिकी सैनिकों की मौत, भारी खर्च और पूरी दुनिया को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है।

इजरायल के साथ जंग में लेबनान को भारी नुकसान, हिजबुल्लाह के 400 लड़ाकों समेत 1100 से ज्यादा लोगों की मौत



नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़े भीषण संघर्ष में लेबनानी सशस्त्र समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 मार्च से इजरायल के साथ भिड़े भीषण संघर्ष में अब तक हिजबुल्लाह के 400 से अधिक लड़ाकें मारे जा चुके हैं।

दरअसल, यह आंकड़ा लेबनान में इजरायल के बढ़ते हवाई और जमीनी अभियान में मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों की

पहली समग्र संख्या है। समूह ने कुछ व्यक्तिगत लड़ाकों के लिए छिटपुट नोटिस जारी किए हैं, लेकिन आ हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर कुल आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। इजरायली सेना ने सूत्रों द्वारा बताई गई संख्या से अधिक संख्या में हिजबुल्लाह के मारे गए लोगों की संख्या बताई है। इजरायली सेना का दावा है कि इस सप्ताह उसने लेबनान में कम से कम 700 हिजबुल्लाह लड़ाकों

को मार गिराया है, जिनमें समूह के कुलीन रादवान बल के सैकड़ों सदस्य शामिल हैं।

नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता स्वास्थ्य मंत्रालय - लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली हमलों और जमीनी अभियानों में लेबनान में 1,142 लोग मारे गए हैं। इनमें 122 बच्चे, 83 महिलाएं और 42 चिकित्सक शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिकों और लड़ाकों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। शुक्रवार को इजरायली सेना ने आकाश में लक्ष्य लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान एक सैनिक और एक लड़ाकू अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले सेना ने कहा था कि दक्षिणी लेबनान में हुई लड़ाई में उसके चार सैनिक मारे गए हैं।

Noida Airport ने किसान को किया मालामाल, 15 करोड़ खाते में आते ही खरीदा हेलीकॉप्टर



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (28 मार्च) को नोएडा में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे जेवर हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। शुरु में सालाना 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट, 70 मिलियन यात्रियों तक विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दिल्ली के IGIA पर भीड़ कम होगी और भारत की विमानन प्रोफाइल को बढ़ावा मिलेगा।

इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बीच नोएडा का एक खबर वायरल हो रही है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की वजह से एक

किसान करोड़पति बन गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण किया था। इससे लोकल निवासियों को बहुत फायदा हुआ है। इसमें कई किसान भी शामिल हैं। एक किसान को करोड़ रुपये मिले और उस पैसों से उसने एक हेलिकॉप्टर खरीदा है। साथ ही वह दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने की प्लानिंग भी कर रहा है।

हालांकि, किसान ने यह दावा नहीं किया है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के उप-ठेकेदारों में से एक जिसका नाम शिवम प्रजापति है उसने यह बात कही।

किसानों की चमकी किस्मत - द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिवम प्रजापति ने कहा- ज्यादातर लोग एयरपोर्ट बनने और उनकी जमीन अधिग्रहित होने से बहुत खुश हैं। सबने अपने शौक-शौक पूरे कर लिए।

आम आदमी को मिलेगी राहत, क्या अगले महीने घटेगी आपकी Home Loan EMI?



नई दिल्ली (एजेंसी)। अगले महीने से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। इसके साथ ही अगले महीने देश की केंद्रीय बैंक, आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की मौद्रिक समिति की बैठक है। इस बैठक के दौरान आरबीआई वित्तीय संभावित कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया जाता है कि रेपो रेट में कोई बदलाव करना है या नहीं।

आपको बता दें कि रेपो रेट का सीधा असर आपके लोन की ईएमआई पर पड़ता है। खासकर तब अगर आपने लोन

प्लॉटिंग रेट पर लिया हो। मसलन अगर रेपो रेट कम हुआ तो प्लॉटिंग रेट भी कम होगा और आपको कम ब्याज के साथ ईएमआई भरना होगा। इसके साथ ही अगर वृद्धि हुई तो ठीक इसका विपरीत होता है।

अब जानते हैं कि क्या अगले महीने आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है या नहीं - मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरबीआई अगले महीने होने वाली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। अगले महीने भी रेपो रेट 5.25% रह सकता है। रिपुटर्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल के मिड तक रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

ऊपर दी गई टेबल के अनुसार आरबीआई द्वारा पिछले साल कुल मिलाकर रेपो रेट में 1.25 फीसदी की कटौती की गई है। पिछले साल में जून में आरबीआई ने सबसे ज्यादा कटौती की थी। फरवरी में सामान्य रह रेपो रेट- इस साल अब तक आरबीआई की बैठक एक बार ही आयोजित हुई है। फरवरी में हुई बैठक के दौरान आरबीआई ने यह तय किया कि वे रेपो रेट में इस समय 5.25 फीसदी चल रहा है। दिसंबर से अब तक रेपो रेट सामान्य रहा। इसके साथ ही आगे भी रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम लग रही है।

अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, तो बैंक कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं। इसी तरह आम आदमी को भी कम ब्याज पर लोन मिल जाता है।

ऐसी ही अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी आती है, तो बैंकों को लोन लेना महंगा पड़ेगा। इससे आप पर होने वाला ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति कि प्लॉटिंग रेट पर होम लोन लिया है तो ऐसे व्यक्ति का ईएमआई रेपो रेट पर निर्भर होता है। अगर आपने फिक्स्ड ब्याज दर पर लोन लिया है तो इस पर रेपो रेट का कम प्रभाव पड़ता है।

क्योंकि यह बैंकों पर भी निर्भर करता है कि रेपो रेट में कटौती के बाद वे फिक्स्ड

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित तोरखम सीमा चौकी को गुरुवार को अस्थायी रूप से खोल दिया गया ताकि सैकड़ों अफगान शरणार्थियों स्वदेश वापस जा सकें। पाकिस्तान में 20 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी हैं।

इस्लामाबाद चाहता है कि वैध वीजा धारकों को छोड़कर सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें। इस बीच अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने गुरुवार को बताया कि नशा मुक्ति अस्पताल पर हुए हमले में मृतकों की संख्या अब 411 हो गई है।

263 लोग घायल हुए हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं। 16 मार्च को पाकिस्तानी ने नशा मुक्ति अस्पताल पर हमला किया था। इस हमले में मारे गए 60 लोगों को गुरुवार को काबुल के कब्रिस्तान में दफनाया गया।

दालमंडी में तीसरी बार शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, एक दिन में ध्वस्त किये जायेंगे 30 मकान, कार्यवाही में शामिल हुआ बुलडोजर

एक महीने बाद ध्वस्ती के कार्यवाही में लगा हाथ चले बुलडोजर, सुरक्षा बाबत भारी फोर्स तैनात रही

दैनिक दिव्य संवाद/वाराणसी। वाराणसी तीसरे चरण में ईद के बाद लगभग एक महीने बाद दालमंडी मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गयी, कार्यवाही में यदि प्रशासन के आकड़े की बात की जाए तो करीब 30 मकानों को ध्वस्त किया जायेगा, होली, ईद और रामनवमी के बाद दालमंडी में ध्वस्तीकरण की यह अब तक की सबसे बड़ा एक्शन है, जिसके लिए दालमंडी को छवनी में तब्दील करके है एक भारी फोर्स तैनात किया गया है। ध्वस्तीकरण में तेजी लाने के लिए बुलडोजर से मकानों को ध्वस्त किया जाना सभी शुरू कर दिया गया है। होली, ईद और रामनवमी के बाद 3.0 में शुरू हुए आज की ध्वस्तीकरण की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है, जहाँ एक साथ 30 भवन पर यह कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, इस



बड़ी ध्वस्तीकरण के लिए दालमंडी में

आज पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पीएससी और सिविल पुलिस की तैनाती करने के साथ ही पूरे कार्यवाही की ज़िम्मे से निगरानी कराई जा रही है, इसके अलावा ध्वस्तीकरण के स्थान पर बैरिकेटिंग कर भीड़ के आने जाने पर रोक लगा दी गयी है। इसे पूरे मामले पर बात करते हुए क्लब्स के एक्स ई एन के के सिंह ने बताया की आज करीब 30 भवन चिह्नित किये गए हैं जिनकी सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद

सभी दुकान खाली करा ली गयी है साथ ही मुआवजा भी दे दिया गया है, अब जबकि ल्यूहार का समय नहीं है ऐसे में आगे के दो महीने रोजाना कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं मौके पर मौजूद एसीपी दशाधमेश डॉ अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि क्लब्स के इस ध्वस्तीकरण अभियान को सकुशल सम्पन्न कराया जा रहा है, बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कराई गयी है, पी एस सिस्टम से लगातार अलाउंसमेंट कराया जा रहा है। एसीपी दशाधमेश बताया की दालमंडी तंग गलियों का हिस्सा है और यहाँ मकानों की हाइट में कई मंजिला है। ऐसे में पहले मकानों पर हथौड़े से मजदूर ध्वस्त कर रहे हैं जब मकान दो मंजिला बच रहा तो उसे बुलडोजर से गिराया जा रहा है। एसीपी ने बताया कि यह कार्यवाही जारी रहेगी।

युवक पर हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एक को भेजा जेल

शाजापुर। कट मारने की बात पर तीन बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुख्य आरोपी को घटनास्थल ले गई और वहां घटना का पूरा जायजा लिया। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि यह घटना करीब तीन दिन पहले मनिहारवाड़ी इलाके में हुई थी। भोईवाड़ी निवासी राजेश केवट (32) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां और भांजी के साथ मेला देखकर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी अमन पठान बाइक से आया और कट मारने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि अमन



पठान ने गाली-गलौज करते हुए तलवार से हमला किया। बचाव के प्रयास में राजेश की कलाई पर चोट आई थी। इसके बाद फर्डम पठान अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। जिसने लकड़ी और लात-चूंलों से राजेश केवट के साथ मारपीट की, जिससे युवक के चेहरे और पेट पर भी चोटें आईं। शोर सुनकर परजिन मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर घायल राजेश को बचाया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस

ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्डम उर्फ बाबू खा (21) को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शनिवार को अजहर उर्फ भूरा (20) और अमन पठान (22) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी का घटनास्थल पर पैदल भ्रमण भी कराया। इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष वाघेला, उप निरीक्षक नवीन बिलावलीया, सर्जिन विक्रम सिंह जाटवा, प्रधान आरक्षक राकेश किरार, आरक्षक संजय पटेल और आरक्षक हेमराज मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्यमंत्री संबल योजना अन्तर्गत 12 हितग्राही हुए लाभान्वित परिवारजनों को मिले 28 लाख

देवास। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा 26 मार्च को संबल योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया गया। प्रदेश की जनकल्याण योजनाओं में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर हितग्राहियों को छिद्रवाड मे आयोजित कार्यक्रम से सिंगल क्लीक कर डीबीटी के माध्यम से लाभ वितरण किया। इसी अन्तर्गत

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता राशि वितरण का लाईव प्रसारण निगम बैठक हाल में देखा एवं सुना गया। निगम बैठक हाल में आहुत कार्यक्रम के अन्तर्गत विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गाेश अग्रवाल के द्वारा 12 हितग्राहियों के परिवारजनों को संबल योजना के अन्तर्गत स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। जिसमें सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख कुल 12 हितग्राहियों को राशि

रूपये 28 लाख के स्वीकृति पत्रों का वितरण हितग्राहियों के परिवारजनों को किया गया। इस अवसर पर पार्षद दिपेश कानुनगो, पार्षद प्रतिनिधि निलेश वर्मा, भाजपा नेता विपुल अग्रवाल, जितेन्द्र जायसवाल, निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी, श्रम विभाग से जयपालसिंह, निगम एनयुएलएम शाखा से विशाल जगताप, सुनिल जोशी, मुजफ्फर अली, रवि चौधरी, राकेश चौहान व बड़ी संख्या में हितग्राहियों के परिवारजन उपस्थित रहे।

काले सोने का तौल शुरू, 8 गांव के 361 किसानों की तुली अफीम

मंडसौर। जिले में अफीम का तौल शनिवार, 28 मार्च से शुरू हो गया है। इसी के साथ अफीम कार्तकारों में भी खुशी का माहौल है। किसान तौल के इंतजार में थे। पहले दिन प्रथम खंड में अफीम तौल शुरू कराया गया है। प्रथम खंड के 8 गांवों के 361 किसानों को पहले दिन बुलाया गया। शनिवार अलसुबह से ही अफीम तौलाई के लिए चहल पहल रही। किसानों ने बारी-बारी से अपनी अफीम कुंडों से निकालकर कटेनर में भरवाईं अफीम तौल के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा टेंट, कूलर और टंडे पानी की व्यवस्था कवाई गई है। गौरतलब है कि मंडसौर, नीमच और जावरा क्षेत्र में अफीम काष्ठ होती है। इनमें

कुल आठ केंद्र बनाए गए हैं। मंडसौर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड हैं तथा एक खंड सीतामऊ में है। जानकारी के अनुसार मंडसौर जिले में कुल 6400 से ज्यादा अफीम उत्पादक किसान हैं। अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। काले सोने के नाम से प्रसिद्ध अफीम को लेकर मंडसौर जिला प्रदेश ही नहीं देश-विदेश में ख्याति प्राप्त है। बताया गया है कि सीपीएस पद्धति वाले किसानों की अफीम तौल बाद में शुरू होगी, जिसका तारीखवार अलग निर्धारित की गई है। अफीम तौल 28 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सभी खंडों से बारी-बारी से चिन्हित गांवों के अफीम कार्तकारों को सूचना देकर

तौल हेतु बुलाया जाएगा। गाढ़ता चेक की गई, सेम्पल नीमच भेजे जाएंगे- अफीम गोदाम स्थित नारकोटिक्स कार्यालय में किसानों की अफीम का गाढ़ता चेक की गई। किसानों की मौजूदगी में सेम्पल भी लिए गए। ये सेम्पल नीमच स्थित ओपियम फेक्टरी की लेब में भेजे जाएंगे। बाद में किसानों को अफीम का भुगतान किया जाएगा। अपने-अपने कुंडों के साथ ट्रेक्टर से पहुंचे किसान- गौरतलब है कि 28 मार्च को बुलाए गए किसानों की अफीम तौलाई होना थी। इसके चलते दलौदा तहसील से संबंधित 8 गांवों के किसानों ने मुखिया के साथ अफीम कुंडों सहित मंडसौर पहुंच गए थे। रात्रि में किसानों ने अफीम की सुरक्षा

की। इसके अलावा अनेक किसान शनिवार सुबह तौलाई केंद्र पर पहुंचे। हर वर्ष अक्सर होती रही है कुंडा लूटने की वारदात- उल्लेखनीय है कि अफीम फसल में लुनाई व चिराई की प्रक्रिया के बाद अफीम एकत्र की जाती है। एकत्र अफीम को किसान कुंडे में भरकर गोपनीय तरीके से रखते हैं और उसकी सुरक्षा भी की जाती है। जब तक अफीम तौलाई नहीं हो जाती, तब तक किसानों को डर सताता रहता है। पूर्व के वर्षों में नजर डालें तो अफीम कुंडों को लूटने की वारदातें होती रही हैं। पिछले वर्ष ही मल्हारगढ़ तहसील के गांव लसुडिया राठौड़ में बुजुर्ग महिला की हत्या कर आरोपी अफीम ले गए थे।

रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं, सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम



संघर्षों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (ईंटा) ने किया है, जिसने इसे सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया। सभा में फिल्म डायरेक्टर, लेखक एवं कवि मनी चौहान ने कहा कि थियेटर को केवल फिल्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक जीवंत मंचीय कला है, जिसमें समाज अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। सांस्कृतिकमि नरेंद्र कुमार त्रिवेदी सूत्रधार ने कहा कि रंगमंच समाज का आईना है और युवाओं को इससे जोड़कर इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। ईंटा सचिव हू बानो

सैफी ने संचालन करते हुए कहा कि सविधान अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी स्पष्ट दस्तावेज है। अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ईंटा उपाध्यक्ष हेमन्त कछवा ने कहा कि संगठन का गौरवशाली इतिहास जन मुहों को नुक़ड नाटक के माध्यम से उठाने की प्रेरणा देता है। अभय मेहता ने भी विचार व्यक्त किए। ईंटा अध्यक्ष शोभा कश्यप ने कहा कि सविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा जैसे अधिकार देता है, साथ ही कानून पालन और भाईचारा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगरीय गायन हुआ, जिसमें नन्द किशोर राठौर, ललित मेहता, राजेश मंडवारिया,संतोष परसाई सहित अनेक लोगों ने सहभागिता की। संचालन हू बानो सैफी ने किया और आभार प्रदर्शन डी.पी. जोशी ने किया।

लगन लाने के बहाने बाईक पर बैठाया, शराब पिलाई, फिर बाईक से बांधकर घसीटा

शाजापुर। ग्राम सिरोलिया निवासी एक व्यक्ति को उसके ही समधी ने बाईक से बांधकर घसीटा। जब लोगों ने बीच बचाव किया तो उसने ग्रामीण की रस्सी तो खोल दी लेकिन उसे जमीन पर घसीटा रहा। इसके बाद उसे अपने हाल पर छोड़कर बाईक से निकल गया। लोगों परिजन को इसकी सूचना दी और घायल को रात 1 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भैंसवा माता मंदिर के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो शनिवार को सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी देवीलाल ने अपने समधी मांगीलाल को रस्सी से बाइक से बांध रखा है और उसे सड़क पर घसीट रहा है। लोगों ने कहा अब मत करो, मर जाएगा- घटना भैंसवा माता मंदिर के पास की है, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ लोग देवीलाल को रोकते हुए और यह



कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब बाइक से मत घसीटो, मर जाएगा। इसके बाद देवीलाल रस्सी खोलकर बुजुर्ग को अलग करता है, लेकिन फिर उसे दोनों हाथों से पकड़कर बेरहमी से जमीन पर घसीटता है। बाद में वह पीड़ित को वहीं छोड़कर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर निकल जाता है। युवक के जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पीड़ित बुजुर्ग की जेब से मोबाइल निकालकर उसके परिजन को घटना की सूचना दी। शुक्रवार रात को

परिजन भैंसवा माता मंदिर पहुंचे और पुलिस वाहन की मदद से मांगीलाल को मक्सी थाने ले गए। यहाँ से इलाज के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार रात करीब 1 बजे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। मामले में अभी तक पुलिस ने किसी पर भी कोई केस दर्ज नहीं किया है। लगन लाने के बहाने ले गया- मांगीलाल के परिजन शंकरलाल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे समधी देवीलाल उनके घर आया। मांगीलाल से लगन लाने के लिए भैंसवा माता मंदिर चलने को कहा। मांगीलाल ने घर पर हवन चलने का हवाला देते हुए मना किया, लेकिन देवीलाल नहीं माना और उन्हें अपने साथ ले गया। वहां जाकर दोनों ने साथ शराब पी। इसके बाद देवीलाल ने मांगीलाल को बाइक से बांधकर घसीटा। परिजन को स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सूचना दी। पुलिस ने उन्हें मक्सी थाने और फिर शाजापुर जिला अस्पताल जाने को कहा।

बुजुर्ग के मर्डर में उसके सगे भाई के दो बेटे और दामाद निकले हत्यारे

मंडसौर। सीतामऊ थाने के तहत साखतली गांव निवासी बुजुर्ग व्यक्ति शंकरलाल पाटीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर हत्यारों को अपने गिरफ्तार में ले लिया है। इसका खुलासा शनिवार दोपहर में कंट्रोल रूम में प्रेसवार्ता के माध्यम से किया गया। हत्यारों और कोई नहीं मृतक शंकरलाल के सगे भाई के दोनों बेटे और दामाद रहे हैं। तीनों जीजा-सालों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या की योजना बनाई और मौका पाकर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह मात्र सात अरि जमीन बनी है, जिसका विवाद लम्बे समय से मृतक और हत्यारों के बीच चला आ रहा था। मामले में दोनों सगे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उनका जीजा फरार है। आरोपी मृतक के छोटे भाई के बेटे



है, जो रिश्ते में भतीजे हैं और फरार आरोपी मृतक के भाई का दामाद है। घटना के एक दिन पूर्व मृतक के लड़के श्यामलाल को फरार आरोपी अर्जुन ने फोन लगाकर धमकी दी थी। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में गरोट एसपी हेमलता कुरील, सीतामऊ

एसडीओपी दिनेश प्रजापति एवं सीतामऊ थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश प्रजापति मौजूद रहे। यहां बताया गया कि 27 मार्च को जीतन पिता शंकरलाल पाटीदार 26 वर्ष के सूचना दी थी। बताया कि साखतली और बिलात्री गांव के बीच कच्चे रास्ते पर उनका खेत है। मेरे पिता शंकरलाल पाटीदार 26 मार्च को रात्रि में 8 बजे के आसपास साईकिल से खेत पर सोने गए थे। मेरी मां घर पर ली। 27 मार्च की सुबह गांव के कन्हैयालाल पाटीदार ने बताया कि उसके पिता शंकरलाल साईकिल सहित रोड किनारे गिरे हुए हैं। जाकर देखा तो पिता लहुलुहान होकर मृत थे। फरियादी जीवन ने बताया कि मेरे पिता शंकरलाल और व उनके

भतीजे बालेश्वर पिता अनांखीलाल पाटीदार के बीच गांव से लगी पुश्तैनी 07 अरि जमीन का विवाद चल रहा है। मामले में पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। सदहियों की तलाश की गई और उनकी धरपकड़ कर कड़ाई से पूछताछ की गई। इस पर आरोपी बालेश्वर पिता अनांखीलाल पाटीदार एवं उसका भाई नानालाल पाटीदार निवासी साखतली ने हत्या करना स्वीकार किया। दोनों ने अपने जीजा नाटाराम गांव निवासी अर्जुन पिता रामनिवास पाटीदार के साथ योजना बनाकर शंकरलाल की हत्या को अंजाम दिया। मामले में कुल्हाड़ी व बाईक जन्ती में ली गई है तथा फरार आरोपी अर्जुन की तलाश की जा रही है। इस कार्य में सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति एवं उपनिरीक्षक ओमप्रकाश राठौर सहित टीम का सराहनीय योगदान रहा है।

जनहित सर्वोपरि : नगरपालिका के 500 करोड़ के बजट बैठक पर कांग्रेस की कड़ी नजर

मंडसौर। मंडसौर नगर पालिका के लगभग 500 करोड़ रुपये के आगामी बजट को लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की मुख्य अगुवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर ने की, जिसमें विधायक विपिन जैन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए आम जनता की मूलभूत सुविधाओं-पेयजल, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था एवं



अन्य आवश्यक सेवाओं-को प्राथमिकता दिलाने पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में शहर की सड़कों की खराब स्थिति, अंधे विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि बजट राशि के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता और

जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। कांग्रेस इन मुद्दों पर सतत निगरानी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर जनहित में आवाज बुलंद करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर ने यह भी कहा कि नगरपालिका में भाजपा की परिषद होने के बावजूद कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर मजबूती से अपनी आवाज उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बजट केवल कागजों तक सीमित न रहकर वास्तव में जनता की जरूरतों के अनुरूप लागू हो।

ईसीसी मेले में नन्हे बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, खेल-खेल में सीखने का मिला अवसर



नीमच। शासकीय माध्यमिक विद्यालय भरभडिया में शनिवार को प्रारंभिक

बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसी) मेला उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। मेले में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने भाग लेकर विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मेला प्रभारी अनिल कुमार तोतला एवं प्रधानाध्यापक बंशीलाल प्रजापति ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और

सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। साथ ही शिक्षा के साथ संस्कारों को आत्मसात कराते हुए उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी लक्ष्य रहा। मेले के दौरान बच्चों ने अलग-अलग स्टॉल के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। खेल-खेल में सीखने की इस पहल ने बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को एचपीवी कार्ड भी वितरित किए गए।

राजस्थान के सांवरिया सेट मंदिर की तरह सजा मां का दरबार

शाजापुर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां राजराजेश्वरी माता मंदिर में चैत्र नवरात्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया और पूरी नवरात्रि में भक्तों ने शक्ति की भक्ति की। अंतिम दिन लाईव प्रसारण का जिम्मा संभालने वाले रोहित विश्वकर्मा की टीम द्वारा दो नजारा दिखाया गया जो नगरवासियों के लिए कभी न भूल

पाने वाला लम्हा बन गया। शुक्रवार को एबी रोड स्थित मंदिर में चैत्र नवरात्री का पर्व नवमी की आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम दिन हुई महाआरती को विशेष व आकर्षक बनाने के लिए रोहित विश्वकर्मा व उनकी टीम द्वारा आकर्षक आतिशबाजी की गई। जिसे देखकर हर किसी ने इसकी

सराहना की। श्री विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने कई दिनों पहले से यह तय कर लिया था कि अंतिम दिन होने वाली महाआरती को वे विशेष बनाएंगे और कुछ अलग करेंगे। विश्वकर्मा की टीम के इस नवाचार की सभी ने सराहना की। सांवरिया सेट की तरह सजाया माता का दरबार -

राजस्थान राज्य में स्थित श्री सांवरिया सेट जी के मंदिर में हर जन्माष्टमी पर प्रभु के जन्मोत्सव पर इसी तरह की आतिशबाजी की जाती है। जिसके साक्ष्य हजारों श्रद्धालु बनते हैं। इसी तर्ज पर इस बार माता के दरबार में आतिशबाजी की गई। यह नजारा देखने के लिए मंदिर में हजारों लोग पहुंचे।